Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
SARKARI YOJANA
PRADHAN MANTRI JAN-DHAN YOJANA
MERA KHATA BHAGYA VIDHATA
अमृत
Atal Mission for Rejuvenation
and Urban Transformation
Pradhan Mantri
mudra
Yojna
Atal
Pension
Yojana
प्रधान मंत्री
आवास योजना-ग्रामीण
Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin
PMAY
PRADHAN MANTRI AWAAS YOJANA
Skill India
कौशल भारत-कुशल भारत
प्रधान मंत्री आवास योजना
ग्रामीण
लोक कल्याण
के चार वर्ष

Edited by

Adarsh Tiwari

Research Associate,

Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

Research Assistance

Abhay Singh

Layout by

LunaCreatives.in

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

9, Ashoka Road, New Delhi- 110001

Web :- www.spmrf.org, E-Mail: office@spmrf.org, Phone: 011- 23005850

CONTENT

09
" नए भारत" की ओर बढ़ता देश
- **अजय धवले**

11
सुशासन बना राजनीति का केंद्रीय बिंदु, आम नागरिकों के मन में बढ़ा आत्मसम्मान एवं विश्वास का भाव
- **भूपेंद्र यादव**

13
बदल रही है ग्रामीण भारत की तस्वीर, देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान
- **नरेंद्र सिंह तोमर**

15
'मोदी सरकार की नीति और नीयत दोनों ठीक हैं, इसलिए जनता का विश्वास बरक़रार है'
- **आशीष रावत**

17
आर्थिक मजबूती, पारदर्शी शासन और कल्याणकारी नीतियों के चार वर्ष!
- **सतीश सिंह**

20
चार सालों में सुशासन और विकास के हर मोर्चे पर कांग्रेस से बेहतर साबित हुई है मोदी सरकार!
-**अभय सिंह**

23
सुरक्षा, विकास और राष्ट्रीय गौरव के चार वर्ष !
- **नवोदित सक्तावत**

26
'इन एक्सप्रेसवे पर फर्राटे भरते हुए आप मोदी सरकार के आधुनिक भारत से रूबरू हो सकते हैं'
- **अजेन्द्र अजय**

29
'इसे मोदी इफेक्ट ही कहेंगे कि 30 महीने का काम 17 महीने में ही पूरा हो गया'
- **रमेश कुमार दुबे**

31
'कांग्रेस बैलगाड़ी की रफ़्तार से योजनाएं लागू करती थी, मोदी बुलेट जैसी तेजी दिखाते हैं'
- **डॉ दिलीप अग्निहोत्री**

33
सुधार की सही राह पर रेलवे, नए क्षितिज पर ले जाने के लिए ढांचागत सुधार की जरूरत
- **अश्विनी लोहानी**

35
Four years of Narendra Modi govt: A pithy and cool micro-site tells and sells 48-month success story
- **Samir Sachdeva**

37
Modi government at four years: It has pushed through a range of structural reforms whose results will show
-**Arvind Panagariya**

39
My Reflections on the NDA Government after Completion of Four Years in Power
- **Arun Jaitley**

भूमिका

यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान देश भ्रष्टाचार, महंगाई, घोटालों, महिला असुरक्षा एवं नीतिविहीनता के अंधकार से गुजर रहा था. देश में एक निराशा का माहौल बन गया था. ऐसी परिस्थिति में देश को एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत थी, जो जनता के मन में यह विश्वास पैदा कर सके कि देश फिर से विकास के पथ पर अग्रसर होने में सक्षम है. अँधेरे के दौर में देश की आवाम ने भाजपा में उजाले की किरण देखी और एनडीए को अपना समर्थन दिया. नरेंद्र मोदी इस प्रचंड जीत के नायक बने. सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक–एक नीतिगत फैसले और जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा देश को गति देने का कार्य प्रारम्भ किया. विकास का पहिया जो ट्रैक से कोसों दूर चला गया था. उसे मजबूती के साथ न केवल ट्रैक पर वापस लाया बल्कि विकास को एक नई रफ़्तार दी. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के चार साल पूरे हो गए हैं. इन चार सालों में सरकार ने जनधन योजना, उज्जवला योजना, मुद्रा, प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिये गाँव, गरीब तथा वंचितों को मुख्यधारा से जोड़कर देश की विकास यात्रा में सहभागी बनाया है, जिसके परिणाम स्वरूप देश न्यू इंडिया की तरफ़ अग्रसर है. केंद्र सरकार के चार साल पूरे होने पर तमाम आलेख, समाचार एवं रिपोर्ट मीडिया संस्थान के माध्यम से प्रकाशित हो रहे हैं. इसे एक जगह संकलित करके एक ई–बुकलेट बनाने की पहल डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी शोध अधिष्ठान द्वारा की गयी है. इस संकलन में जितने भी लेख, रिपोर्ट, खबर लिए गए हैं. सभी लेखों, खबरों एवं रिपोर्टों के लिए अधिष्ठान सभी लेखकों, पत्रकारों, प्रकाशकों, अख़बारों, वेबपोर्टलों एवं पत्रिकाओं के प्रति आभारी है.

डॉ अनिर्बान गांगुली

(निदेशक, डॉ श्यामा प्रसाद मुकर्जी शोध अधिष्ठान)

Narendra Modi
@narendramodi

On this day in 2014, we began our journey of working towards India's transformation.
Over the last four years, development has become a vibrant mass movement, with every citizen feeling involved in India's growth trajectory. 125 crore Indians are taking India to great heights.

I bow to my fellow citizens for their unwavering faith in our Government. This support and affection is the biggest source of motivation and strength for the entire Government. We will continue to serve the people of India with the same vigour and dedication.

पिछले 4 वर्षों में दशकों से विकास से दूर गरीब,पिछड़ों,वंचितों और किसानों के द्वार तक सरकार और उसकी जनकल्याणकारी योजनाओं को ले जाकर सम्पूर्ण विश्व में भारत को गौरवान्वित करने वाली मोदी सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी व उनके मंत्रिमंडल को बधाई.

Amit Shah
@AmitShah

अपने अथक परिश्रम से सरकार और पार्टी के बीच एक आदर्श समन्वय की परम्परा को मजबूती देने और मोदी सरकार के जनकल्याण के सन्देश को घर-घर पहुंचाने के लिए भाजपा के पदाधिकारियों और करोड़ों कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई व आभार. #SaafNiyatSahiVikas

Arun Jaitley
@arunjaitley

In the last 4 years leadership of PM @narendramodi ji has transformed India from being a part of the "fragile five" to a "bright spot" on the global economic scene. A regime of policy paralysis has been transformed into one of decisions and actions.

पिछले 4 वर्षों में मोदी सरकार के नेतृत्व में देश का सर्वांगीण विकास हुआ है, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है, आर्थिक, सामाजिक एवं वैश्विक स्तर पर देश सशक्त हुआ है, और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार पर लोगों का विश्वास बढ़ा है. #SaafNiyatSahiVikas

Piyush Goyal
@PiyushGoyal

सरकार की प्रमुख योजनाएं :-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना – इस योजना से अबतक 3.50 करोड़ से अधिक किसान जुड़ चुके हैं. इसके द्वारा किसानों को 11 हज़ार करोड़ रूपए से अधिक की धनराशी क्लेम के रूप में वितरित की गयी है.

ई-नाम - इस पोर्टल से देश की 585 विनयमित थोक मंडियों को जोड़ने के लिए 200 करोड़ रूपए के आवंटन के साथ इसकी शुरुआत हुई. अबतक16 राज्यों और 02 केंद्र शासित प्रदेशों कि 585 मंडियों को इससे जोड़ा जा चुका है.

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - प्रत्येक बूंद अधिक फसल के उद्देश्य से वर्तमान सरकार द्वारा अधिक धनराशी देकर अधिक क्षेत्रफल को सिंचित किया गया है. इसके लिए अबतक 5460.12 करोड़रुपये की अतिरिक्त राशि दी गयी है.

राष्ट्रीय गोकुल मिशन - पहली बार देशी नस्लों के संवर्धन और संरक्षण हेतु 20 गोकुल ग्राम कि स्वीकृति 196 करोड़ रूपए के आवंटन के साथ की गयी. जून 2017 में गोपाल रत्न से 10 किसानों को और 12 संस्थाओं को कामधेनु पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - इससे दलहन उत्पाद में हुई वृद्धि. 2015-16 में दलहन का उत्पादन 16.35 मिलियन टन रहा था, जो कि वर्ष 2017-18 में 46% वृद्धि के साथ 23.95 मिलियन टन हो गया.

सॉयल हेल्थ कार्ड - इससे मृदा जाँच करके भूमि को फसल उगाने के लिए अत्यधिक उपयोगी बनाने की जो शुरुआत हुई, उसका लाभ आज खाद्यानों के उत्पादन में हुई बढ़ोत्तरी के रूप में सामने है. अबतक सरकार 14.20 करोड़ से अधिक कार्ड का वितरण कर चुकी है.

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एकीकृत बागवानी मिशन के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि सतत बागवानी को बढ़ावा देने, किसानों को मंडी से जोड़ने तथा किसानों के संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के स्वामित्व को बढ़ावा देना उद्देश्य है.

कृषि के क्षेत्र में सरकार द्वारा अनेक कार्य किये गए हैं -

- न्यूनतम समर्थन मूल्य को डेढ़ गुना करके, किसानों के हित के लिए सरकार ने यह साहसिक फैसला लिया है.
- हर खेत को पानी के लिए 50,000 करोड़ के खर्च से अबतक 28.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को सिंचित क्षेत्र में दायरे में लाया गया है.
- 5000 करोड़ का माइक्रो इरिगेशन फंड तय किया गया है.
- E-NAM के अंतर्गत 87 लाख से ज्यादा किसान पंजीकृत होकर इसका लाभ उठा रहे हैं.

अन्य योजनायें :-

प्रधानमंत्री जनधन योजना - इस योजना के अंतर्गत 31.56 करोड़ बैंक खाते खोले गए. योजना के माध्यम से वंचित वर्ग को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया और अब सीधे इनके खाते में पैसे जमा किये जा रहे हैं.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना - प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से स्वरोजगार को मिल रहा बढ़ावा. योजना में अबतक 12.33 करोड़ रूपए स्वरोजगार के लिए दिए गए और इससे लाभान्वित अब खुद के साथ ही अन्य लोगों को भी रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं.

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना- इसके माध्यम से 18,374 गांवों का विधुतीकरण कार्य संपन्न हुआ है.यह मोदी सरकार की कार्य संस्कृति का ही परिणाम है कि यह लक्ष्य तय समय के पहले ही हासिल कर लिया गया. सरकार ने देश के सभी गांवों को बिजली देने का कार्य पूर्ण कर लिया है और जल्द ही अपने हर घर बिजली पहुँचाने के लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेगी.

स्वच्छ भारत मिशन - स्वच्छता मिशन के तहत 7.15 करोड़ घरों में शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है. यह विडंबना थी कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी में हम अपने देश में पूर्णरूप से शौचालय बनाने का कार्य नहीं कर पाए थे. लेकिन वर्तमान की भाजपानीत सरकार ने यह काम लिया है और जिसके नतीजे भी सकारात्मक मिल रहे हैं.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना - सरकार की सबसे सफल और लोकप्रिय योजनाओं में से एक. उज्ज्वला योजना से हर घर को फ्री गैस कनेक्शन देने का कार्य मोदी सरकार ने प्रारंभ किया था और सरकार की इस योजना ने महिलाओं के सशक्तिकरण का काम बखूबी किया है. उज्ज्वला योजना के तहत अबतक 3.85 करोड़ गैस सिलिंडर वितरित किये जा चुके हैं और सरकार ने इसके सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इसके लक्ष्य को 5 करोड़ से बढाकर 8 करोड़ कर दिया है.

उजाला योजना - उजाला योजना के माध्यम से सरकार

ने एलईडी बल्ब वितरित करने का कार्यक्रम शुरू किया और कम दामों पर योजना में अबतक 29.90 करोड़ बल्ब कम दामों में लोगों को देने का काम हुआ है.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से देश के हर गाँव को जोड़ने का कार्य चल रहा है. इसमें अबतक 1.40 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है.

स्टार्टअप इंडिया - इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गयी. अबतक 2 लाख से अधिक लोगों ने स्टार्टअप इंडिया लर्निंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया है. 31 मार्च 2018 तक 8765 स्टार्टअप को चिन्हित किया जा चुका है. जिसमें स्टार्टअप के डायरेक्टर्स की बात करें तो 35 प्रतिशत इसमें महिलाएं हैं.

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान - इसके द्वारा पंचायती संस्थानों के सतत विकास के लिए अभियान चलाया गया है. इसमें देशभर में 2.55 लाख पीआरआई कार्य करेंगे.

मोदी सरकार आने के बाद देश में एफडीआई में भी तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है. 2012-13 में जहाँ 34.3 बिलियन डॉलर का आंकड़ा था, वह बढ़कर 60.08 पर पहुँच गया.

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य भी तेजी से हो रहा है वर्तमान में जहाँ 27 किलोमीटर सड़क का निर्माण प्रतिदिन हो रहा है, उसे 2018-19 में 45 किलोमीटर प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर - सरकार ने डीबीटी के माध्यम से देश की आम जनमानस को यह एहसास कराया कि वह सीधे तौर पर सरकार से जुडी हुई है. जिसके हक का जो पैसा है वह सीधे उसके खाते में जाने लगा. जिससे बिचौलियों का राज समाप्त हुआ ,देश में पारदर्शिता की नई शुरुआत हुई.आज इस कारगर नीति के कारण 83,000 करोड़ रूपए की बचत देश को हुई है. वर्तमान में सरकार की लगभग 433 स्कीम इससे जुडी हुई हैं.

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ - बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान से महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ते कदम. योजना के अंतर्गत बालिकाओं के लिए छात्रवृत्तियां का प्रावधान. इसके अतिरिक्त योजना का लाभ यह हुआ कि 146 जिलों में अस्पतालों में प्रसव संख्या में बढ़ोतरी हुई.

प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना - इस योजना के अंतर्गत 1.26 करोड़ से अधिक बालिकाओं के खाते खोले गये. जिनमें करीब 20,000 करोड़ रूपए जमा हुए. इसके अलावा बालिकाओं के प्रति अपराध के खिलाफ कड़े कानूनों का प्रावधान रखा गया है.

देश के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य प्रगति पर है. इसके लिए देशभर में 13,000 करोड़ केंद्र खोले गए हैं.

आयुष्मान भारत - यह विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है.इसमें करीब 50 करोड़ लोगों को प्रति परिवार 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज दिया जायेगा. इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 1.5 लाख उप-केन्द्रों और स्वास्थ्य केन्द्रों को कल्याण केन्द्रों में परिवर्तित किया जा रहा है.

प्रधानमंत्री आवास योजना - हर परिवार को 2022 तक घर सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई. अबतक योजना के तहत 1 करोड़ घरों का निर्माण हो चुका है.

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में रेलवे के विकास ने पकड़ी गति. ट्रैक नवीनीकरण में 2013-14 के 2,926 किमी के मुकाबले 2017-18 में 4,405 किमी के साथ हुए 50% की वृद्धि. रेल दुर्घटनाओं में भी आई 62% की कमी.

स्टैंडअप इंडिया - इस योजना के द्वारा महिलाओं को पूरक कौशल और पूंजी की आपूर्ति की जा रही है. इस पहल के अंतर्गत एससी/एसटी/ओबीसी महिला उद्यमियों को 1 करोड़ रूपए तक के ऋण का प्रावधान है.

डिजिटल इंडिया - इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकार के कार्यों में पारदर्शिता लाना है, सरकार को जनता से जोड़ना, लालफीताशाही का अंत करना है. इसके तहत 5 करोड़ ग्रामीणवासियों को इन्टरनेट सुविधा देने के लिए वाईफाई हॉटस्पॉट बनाये जायेंगे. 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' से अबतक 1 करोड़ लोगों को साक्षर किया जा चुका है. डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने में भीम ऐप का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है.

" नए भारत" की ओर बढ़ता देश

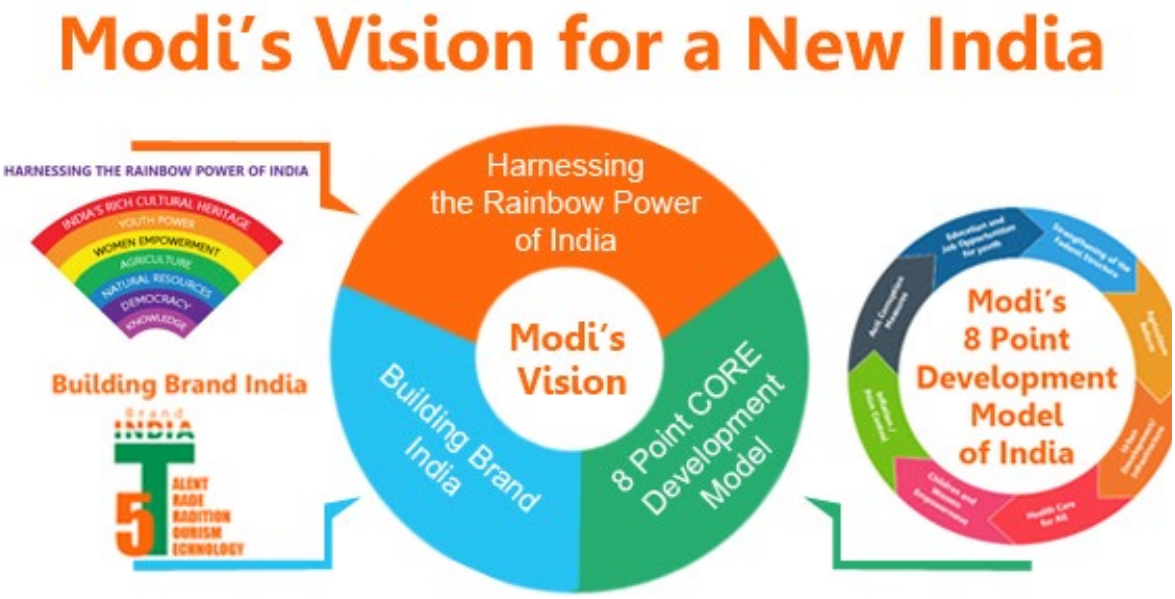

अजय धवले

26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तथा अपने पहले ही दिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि सामाजिक बदलाव उनकी सरकार का मिशन है और सरकार लोगों के जीवन स्तर को उपर उठाने के लिए लगातार काम करेगी. हाल ही में भाजपा प्रणीत एनडीए सरकार ने 4 साल पूर्ण किये हैं एवं जिस तरह आज जनमानस में मोदी सरकार ने साख बनाई है उससे यह दिखता है की उनकी सरकार ने अपनी मंशा रूप में काम किया है.

मोदी सरकार का उद्देश्य अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को ध्यान में रखकर योजना बनाना है. उसी का नतीजा है कि नीति आयोग ने पूरे देश में 105 ऐसे जिले छांटे, जो अन्य जिलों के मुकाबले पिछड़े हुए थे. इन जिलों में शिक्षा, चिकित्सा, पानी-बिजली, कुपोषण समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया और दिनोंदिन स्थिति में सुधार आ रहा है. प्रधानमंत्री ने 125 करोड़ लोगों का विश्वास जीता है और परिवारवाद, तुष्टीकरण और वोटबैंक से हटकर विकास की राजनीति की शुरुआत की है. आज जनधन योजना, मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, फूड सिक्योरिटी, फसल बीमा योजना, महिला सशक्तिकरण, स्किल डेवलपमेंट, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला, पीएम आवास, पीएम सुरक्षा बीमा जैसी योजनाओं की बदौलत भारत ग्लोबल इंडेक्स में काफी अच्छी स्थिति में पहुंचा है.

हम उदाहरण के तौर पर उज्जवला योजना को लें तो उज्ज्वला योजना समाज में बदलाव लेकर आयी है और इसके चार करोड़ लाभार्थियों में से 45 फीसदी दलित और आदिवासी हैं. मोदी सरकार की अहम कल्याणकारी इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों तक एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराना है. वर्ष 2014 तक देश के 13 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मिले थे किन्तु पिछले चार वर्षों में 10 करोड़ नए कनेक्शन दिए गए. आज देश के 70 फीसदी गांवों में एलपीजी की पहुंच 100 प्रतिशत है और 81 प्रतिशत गांवों में 75 फीसदी से ज्यादा है. स्वच्छ ईंधन से स्वस्थ भारत का निर्माण हो रहा है. हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने उज्जवला योजना के लाभार्थियों से बातचीत की. जिसमें कश्मीर के अनंतनाग के महिलाओं के एक समूह ने उन्हें बताया, यह रमजान का महीना है हम रोज पवित्र कुरान

पढ़ते हैं. हम रोज आपके लिए दुआ करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रधानमंत्री बने रहेंगे.

हम जनधन की बात करें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर व्यक्ति के लिए बैंकिंग सुविधाओं के द्वार खोलना रहा है. सरकार चाहती है कि इस देश में कोई ऐसा परिवार ना हो जिसका अपना बैंक खाता ना हो. इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को हुई थी और 25 अप्रैल 2018 तक इस योजना के तहत 31 करोड़ 52 लाख खाते खोले जा चुके हैं. इन खातों में अब तक 80871.67 करोड़ की धनराशि जमा हो चुकी है.

हम, बात करें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तो यह योजना मुद्रा बैंक के तहत शुरू की गई है. जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है. इसके तहत सरकार बिना किसी गारंटी के लोन देती है. इस योजना को शिशु, किशोर और तरुण तीन भागों में बांटा गया है. शिशु में 50 हजार, किशोरों में 50 हजार से 5 लाख और तरुण में 5 लाख से 10 लाख का लोन सरकार से लिया जा सकता है. 2018-19 के आम बजट में इस लोन की राशि 3 लाख करोड़ बढ़ा दी गई है. अब इस योजना का बजट 220596.05 करोड़ हो गया है. सरकार इस योजना के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है जिसमें काफी हद तक वह सफल भी रही है.

30 जून 2017 की आधीरात से लागू हुआ और 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ जीएसटी एक राष्ट्र, एक कर, की और एक बड़ा कदम है. इसके आने से राज्य वैट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, खरीद कर और प्रवेश कर जैसे कई राज्य और केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों को एक में सम्मिलित कर दिया गया है.

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के देश के उच्च वर्ग के सतत विरोध व विपक्ष की कड़ी आलोचनाओं के बीच राष्ट्र सर्वोपरि ध्येयवाक्य के साथ अपने निरंतर फैसले लेते रहने की जिद से देश में एक सामाजिक बदलाव का आंदोलन खड़ा किया है.

राष्ट्र सर्वोपरि और सबका साथ-सबका विकास के सुवर्णमध्य को साधते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ देश की आम जनता के व्यव्हार परिवर्तन की जो प्रक्रिया मोदी सरकार ने शुरू की है, इसके परिणाम अंततरू सकारात्मक ही मिलने हैं. ई-गवर्नेंस, ई-टेंडरिंग, डिजिटलीकरण और जीएसटी इन 4 उपक्रमों ने देश और समाज की दिशा, सोच, कार्यपद्धति और निष्पादन सबको बदल दिया है सच तो यह है कि नए भारत का उदय हो चुका है. देश इस समय चहूंओर व्यापक बदलावों का साक्षी है, घोटालों एवं भष्टाचार की जगह विकास की बात हो रही है.

आज चार वर्ष पूर्ण होने पर जब हम उपलब्धियों की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो बात मन में आती है वह यह है कि देश आत्मनिर्भर बन रहा है.

2019 के आम चुनावो में हम, श्देश का बढ़ता जाता विश्वास... साफ नीयत, सही विकास के नारे के साथ जब देश की जनता के सामने जायेंगे तो वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जो बदलाव हुए हैं वह महसूस करते हुए हमें और भी गर्व होगा क्योंकि ‘‘पिछले चार वर्षों में, विकास एक जीवंत जन आंदोलन बन गया है, देश का हरेक नागरिक भारत के विकास पथ से अपने को जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है.

(लेखक कॉर्पोरेट लॉयर हैं)

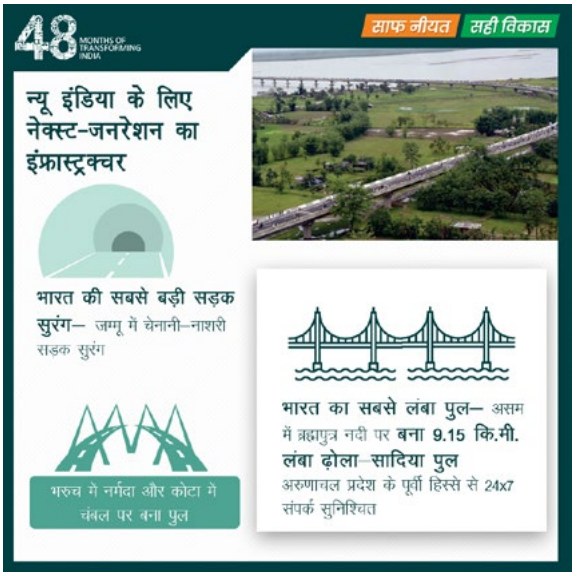

सुशासन बना राजनीति का केंद्रीय बिंदु, आम नागरिकों के मन में बढ़ा आत्मसम्मान एवं विश्वास का भाव

भूपेंद्र यादव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के चार वर्ष पूरे हुए. इस कार्यकाल में मोदी सरकार ने जहां आम जनता से प्रभावी संवाद स्थापित किया वहीं आर्थिक निर्णयों एवं गरीब कल्याण कार्यक्रमों की सफलता और सामाजिक विषयों के प्रति जागरूकता ने देश के आम नागरिकों के मन में आत्मसम्मान एवं विश्वास का भाव बढ़ाया है. यही कारण है कि चार वर्षों में जन सामान्य की राजनीतिक विषयों में सक्रियता बढ़ी है. आम जन के मुद्दों से लेकर उत्तर-पूर्व के चुनाव तक के मसले राष्ट्रीय राजनीति की चर्चा के केंद्र बने हैं. जहां आम जन की अपेक्षाओं में वृद्धि हुई है वहीं युवा वर्ग में भारतीयता का भाव प्रभावी हुआ है. भाजपा का विभिन्न राज्यों में विस्तार जनभावना के सकारात्मक होने को दर्शाता है. मोदी सरकार के इन चार वर्षों के कार्यकाल को चार विषयों एवं उपलब्धियों में विभाजित करके देखा जा सकता है.

पहला, सुशासन का विषय देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बना है. दूसरा, सामाजिक विषयों पर सरकार एवं जनता का संवाद बढ़ा है. तीसरा, समाज के हाशिये पर खड़े वर्गों का सशक्तिकरण हुआ है. चौथा, विश्व में भारत की साख में वृद्धि हुई है. किसी भी सरकार के सुशासन का पहला मानक होता है उसकी योजनाओं को एक निश्चित प्रकार्यावधि में पूरा किया जाना केंद्र सरकार ने उज्ज्वला, उजाला, जन-धन, मुद्रा जैसी योजनाओं को एक तय समय में पूरा किया है. सुशासन का दूसरा मानक है चुनौतियों का साहस के साथ सामना करना और जनता के अधिकतम कल्याण के विषयों पर साहस भरे निर्णय लेना. केंद्र सरकार ने नोटबंदी, जीएसटी लागू करने के साथ कड़े कानून के माध्यम से कालेधन के खिलाफ सख्ती से करवाई की है. सुशासन का तीसरा मानक हैजड़ हो चुके कानूनों को समाप्त करके प्रभावी कानूनों एवं नीतियों को लागू करना.

इसीलिए आधार जैसे कानून के माध्यम से गरीब व्यक्तियों के हक को सुनिश्चित किया गया है. दिवालिया कानून लाकर विश्व समुदाय में भारत की साख को व्यवस्था के माध्यम से सुधारने का काम हुआ. आज कारोबारी सुगमता में भारत की रैंकिंग सौवें स्थान पर है. पहले भारत एक सौ तीसवें स्थान पर था. भूषण स्टील की बिक्री के जरिये बैंकों का पैसा, कर्मचारियों का वेतन

और सरकार के पैसे दिवालिया कानून के माध्यम से वापस लिए गए. हालांकि केंद्र सरकार के सुशासन को हर विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने मुद्दा बनाया, पर न तो जनता ने उनका समर्थन किया और न ही किसी कानून को लागू करने के बाद सरकार को पीछे मुड़कर देखना पड़ा. विपक्ष की ओर से भले ही जातिवाद, संप्रदायवाद, वंशवाद की राजनीति का सहारा लेकर और विभेद पैदाकर जनता को उकसाने का काम किया जा रहा हो, लेकिन देश आज सुशासन को ही शासन में आने की कसौटी मान रहा है. सुशासन को राजनीति का केंद्रबिंदु बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बड़ी उपलब्धि है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जनता के साथ प्रशासनिक स्तर के औपचारिक संबंध ही नहीं रखे, बल्कि सामाजिक कुरीतियों से लड़ने में जन भागीदारी को भी बढ़ाया. इसका सबसे बड़ा उदाहरण सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वच्छता का कार्यक्रम है. स्वच्छता पर प्रधानमंत्री के आग्रह से आज आम नागरिकों में सार्वजनिक स्थानों में सफाई का भाव बढ़ा है. स्वच्छता को लेकर देश की इच्छाशक्ति मजबूत हुई है. बीते चार वर्षों में योग दिवस जैसे आयोजनों में भी जन भागीदारी में भारी वृद्धि हुई है. इसके अलावा डिजिटल पेमेंट के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ी है. प्रधानमंत्री द्वारा वैश्विकमंचों पर जिस प्रकार हिंदी का प्रयोग किया गया उससे देश के ग्रामीण युवाओं में भी आत्मविश्वास के भाव की वृद्धि हुई है. भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यस्थलों पर सुरक्षा कानून लागू किया गया और मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया. सैन्य बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका से सामाजिक जीवन में महिलाओं के सक्रिय होने का माहौल बना है. इसी कारण स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्राम विकास, नारी सुरक्षा जैसे मामलों पर जनता ने सरकार के साथ मिलकर कदम बढ़ाया.

मेरा अनुभव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 'मन की बात' के माध्यम से नौजवानों के कॅरियर, किसान, कृषि, ग्रामीण विकास और सामान्य व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार आदि विषयों पर बात होने से लोगों में राष्ट्र निर्माण के प्रति भागीदारी और सरोकार की भावना को और बल मिला है. यह दूसरी उल्लेखनीय उपलब्धि है. तीसरी उपलब्धि समाज के हाशिये पर खड़े लोगों का सशक्तीकरण करना है. उज्ज्वला योजना के तहत जहां गरीब के घरों में गैस सिलेंडर पहुंचाया गया वहीं शौचालयों का निर्माण कराकरएक बड़े वर्ग को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया गया है. सरकार ने गरीबों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए हैं. पिछले 70 सालों के शासनकाल में कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित रखा. इस बार जब अन्य पिछड़ा वर्गों यानी ओबीसी के संवैधानिक आयोग का विषय आया तो कांग्रेस ने विरोध किया. इससे कांग्रेस की कुटिल राजनीति उजागर होती है. लोकतंत्र की मजबूती 'सबका साथ सबका विकास' से ही संभव है. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सुशासन की उस धारणा को विकसित किया जिसने देश की अपेक्षाओं में वृद्धि की है.सत्ता में आते ही अपने शपथ-ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षेस देशों के प्रमुखों को आमंत्रित कर सबके साथ मधुर संबंध रखने की अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया था. साथ ही, एशिया में भारत के मजबूत होते नेतृत्व का संदेश भी दिया था. अब यह संदेश एशिया से निकलकर विश्व भर में प्रसारित हो रहा है और विभिन्न वैश्विक मंचों पर यह स्पष्ट हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक मजबूत देश के रूप में उभर रहा है. इसी वर्ष जनवरी में दावोस के मंच से विश्व के तमाम देशों के शासनाध्यक्षों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी का उद्घाटन भाषण विश्व समुदाय में भारत के मौजूदा नेतृत्व की स्वीकार्यता को दर्शाता है. इस भाषण में जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्या पर प्रधानमंत्री ने जो स्पष्ट दृष्टिकोण रखा उसने विश्व समुदाय के समक्ष यह सिद्ध कर दिया कि अब किसी भी बड़े वैश्विकमसले पर भारत नेतृत्व करने में सक्षम हो चुका है. यह भी उल्लेखनीय है कि इस वक्त भारत के विश्व के सभी देशों से मधुर संबंध हैं.

एशिया की बात करें तो इसी साल गणतंत्र दिवस पर आसियान देशों के सभी शासनाध्यक्षों को आमंत्रित करके प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि एशिया में भारत ही बड़ा भाई है तो वहीं ब्रिक्स सम्मेलन के जरिये वैश्विक प्रभाव का संदेश दिया. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति ने सफलता के नवीन आयाम स्थापित किए हैं और मोदी विश्व पटल पर एक प्रभावी नेता के रूप में उभरे हैं. कुल मिलाकर लोक कल्याण का विषय हो या राष्ट्रीय सुरक्षा का अथवा राष्ट्रीय गौरव का, सभी मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकासपथ पर सतत अग्रसर है.

(लेखक राज्यसभा सदस्य एवं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं,दैनिक जागरण से साभार)

बदल रही है ग्रामीण भारत की तस्वीर, देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान

credit : www.himachaldastak.com

नरेंद्र सिंह तोमर

हालांकि गांव, गरीब और किसान सभी सरकारों की प्राथमिकता सूची में रहे हैं, लेकिन इसे एक मिशन का रूप देने का श्रेय मोदी सरकार को जाता है. यह सरकार गांव, गरीब और किसानों को ऊपर लाने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ग्रामीण विकास विभाग का बजटीय प्रावधान 2012-13 में 50,162 करोड़ रुपये था, जिसे 2018-19 में बढ़ाकर 1,12000 करोड़ रुपये कर दिया गया. नाबार्ड से लिए गए कर्ज को मिलाकर यह प्रावधान 1,24000 करोड़ रुपये हो जाता है. गांव के हर व्यक्ति के पास अपनी छत का सपना पूरा करने की प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजना के तहत 2022 तक हर पात्र व्यक्ति को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.2017-18 में कुल 44.53 लाख आवास पूरे कर लिए गए. मार्च, 2019 तक एक करोड़ मकान बना लिए जाएंगे. संप्रग सरकार के दौरान 2010-11 से 2013-14 तक 25.51 लाख मकान बनाए गए थे. इसके मुकाबले मौजूदा राजग सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल में 106.8 लाख मकान पूरे कर लिए हैं. गांवों की जीवन रेखा मानी जाने वाली सड़कों के विकास और विस्तार की दिशा में भी केंद्र सरकार ने उल्लेखनीय काम किया है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मार्च, 2018 तक कुल 1,52,165 बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ा गया है, जो कुल बसावटों का लगभग 85 प्रतिशत है. प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को साल में कम से कम सौ दिन का गारंटीयुक्त रोजगार उपलब्ध कराने की योजना मनरेगा के तहत अब कृषि क्षेत्र के विकास और जल संरक्षण पर पर्याप्त बल दिया जा रहा है. आवंटित निधियों की 68 प्रतिशत धनराशि कृषि से जुड़ी गतिविधियों पर खर्च की गई है. बीते तीन वर्षों में 1.43 लाख हेक्टेयर भूमि को जल संरक्षण का लाभ पहुंचाया गया है.

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 2.84 करोड़ संपत्तियों की जियो-टैगिंग की जा चुकी है. संप्रग सरकार ने 2010-11 से 2013-14 तक मनरेगा पर लगभग 1,58,730 करोड़ रुपये खर्च किए थे, जबकि मौजूदा सरकार ने वर्ष 2014-15 से चार साल की अवधि में 2,02,379 करोड़ रुपये खर्च किए, जो पिछली सरकार के मुकाबले लगभग 27.5 प्रतिशत अधिक

है. इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 53.45 प्रतिशत हो गई है. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत पांच लाख 73 हजार लोगों को प्रशिक्षण दिया गया और तीन लाख 54 हजार लोगों को रोजगार दिलाया गया.2018-19 के दौरान सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आजीविका विस्तार और आधारभूत ढांचे के विकास पर 14.34 लाख करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-दीनदयाल अंत्योदय योजना का विस्तार 584 जिलों के 4456 ब्लॉकों तक कर दिया गया है. इसके तहत स्व-सहायता समूहों की संख्या लगभग 41 लाख हो गई है. चार करोड़ 80 लाख महिलाएं इन समूहों में भागीदारी कर रही हैं. यह एक अच्छा संकेत है कि इस योजना में मौजूदा समय में गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी एनपीए 2.4 प्रतिशत से भी कम हैं.2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण कार्यक्रम की शुरुआत के बाद देश के ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता का दायरा 2014 के 39 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में लगभग 84 प्रतिशत हो गया है.2014 में खुले में शौच जाने वाले लोगों की आबादी 55 करोड़ थी जो जनवरी, 2018 में घटकर केवल 25 करोड़ रह गई. कुल 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं. अक्टूबर, 2014 से अब तक सात करोड़ 25 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है. देश के 386 जिले और लगभग तीन लाख 70 हजार गांव खुले में शौच से मुक्त घोषित कर चुके हैं.

गांव, गरीब और किसान के जीवन स्तर में सुधार से जुड़ी विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में 2,48,160 ग्राम पंचायतें, 6,284 ब्लॉक पंचायतें और 595 जिला पंचायतें पूरे मनोयोग से लगी हुई हैं. प्रधानमंत्री ने 14वें वित्त आयोग की दो लाख 292 करोड़ रुपये से अधिक राशि सीधे पंचायतों को देने की स्वीकृति प्रदान की है. यह राशि 13वें वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत राशि से लगभग तीन गुना अधिक है.2014-15 से 2017-18 केदौरान राज्यों को 1,02,023करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं. यह उत्साहित करने वाला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों और स्थानीय स्तर पर नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है. आज 14.39 लाख महिला पंचायत प्रतिनिधि, गांव और कस्बों का नक्शा बदलने के लिए काम कर रही हैं. मोदी सरकार मार्च, 2022 तक लगभग 5.50 लाख गांवों को वाई-फाई सुविधा से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है. भारत नेट परियोजना के तहत पहले चरण में 21 जनवरी, 2018 तक 1,11,000 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी गई है.

सरकार पूरे देश में डेढ़ लाख स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र भी खोलने जा रही है. मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का निर्माण और वंचित रह गए बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है. अब तक तीन करोड़ 14 लाख बच्चों और 80 लाख 64 हजार से अधिक गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण किया जा चुका है. सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को विशेष महत्व दे रही है. अनुसूचित जातियों के लिए मौजूदा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 56,618.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए मौजूदा वर्ष के दौरान 39,135 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. दिव्यांग-जनों को सहायता उपकरण इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार ने 622.45

करोड़ रुपये खर्च किए हैं. प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अब तक 31 करोड़ 80 लाख 54 हजार से अधिक खाते खोले जा चुके हैं और उनमें 81,200 करोड़ रुपये से अधिक राशि जमा हो चुकी है.23 करोड़ 35 लाख से अधिक खातों को आधार से जोड़ दिया गया है.10 मई, 2018 तक 19,679 गांवों में से 18,374 गांवों का विद्युतीकरण कार्य पूरा किया जा चुका है. इससे गांवों में विकास की गति बढ़ी है.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 13 करोड़ 49 लाख लाभार्थी बीमा करा चुके हैं. इसके तहत 16,469 दावों का निपटारा किया जा चुका है और 328 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में अब तक पांच करोड़ 33 लाख लाभार्थियों का बीमा हो चुका है.19,082 दावों के निपटान हेतु 1802 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत अब तक 41 लाख परिवारों को बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं. अब तक 29 करोड़ 90 लाख एलईडी बल्ब भी बांटे जा चुके हैं. ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने वाली योजनाओं की कामयाबी से मुझे विश्वास है कि ग्रामीण क्षेत्र नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान करने को तैयार है.

(लेखक केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायतीराज स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री हैं. दैनिक जागरण से साभार)

'मोदी सरकार की नीति और नीयत दोनों ठीक हैं, इसलिए जनता का विश्वास बरक़रार है'

आशीष रावत

26 मई, 2014 का दिन था, जब नरेंद्र दामोदरदास मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. आज (26 मई, 2018) उनके कार्यकाल को 4 वर्ष पूरे हो गए हैं.16 मई, 2014 वो तारीख थी, जिस दिन आम चुनावों के बाद हिन्दुस्तान की नई सियासी इबारत लिखी जा रही थी. लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया था और विशाल बहुमत के साथ एक गैरकांग्रेस दल की सरकार बनने जा रही थी.

इस तारीख के बाद लोगों के चेहरे पर रौनक के साथ-साथ एक उम्मीद थी. पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो लगातार हिन्दुस्तान की पीठ में छुरा घोंपता रहा है, वो भी हैरान था; क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में जनमत पर सवार होकर एक 'चाय बेचने वाला' प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठने जा रहा था. नरेंद्र मोदी की सफलता का एक बड़ा कारण यह था कि देश की जनता कांग्रेस के शासनकाल के घोटालों से तंग आ चुकी थी. यूपीए शासनकाल के घोटाले कांग्रेस को 2014 के लोकसभा चुनावों में ले डूबे.वर्ष 2014 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की जोड़ी राज्य-दर-राज्य विधानसभा चुनावों की जीत अपने खाते में लिखवाती चली गई. इसके साथ ही नरेंद्र मोदी का राजनीतिक आधार भी लगातार फैलता रहा. कुल मिलाकर अब यह कहा जा सकता है कि भारत की आधी से भी अधिक आबादी पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता चल रही है. इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिया है.

2014 के लोकसभा चुनावों के बाद हुए तमाम राज्यों के चुनाव केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लोक-कल्याणकारी कामों और नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़े गए, जिनमें ज्यादातर में भाजपा विजयी होकर सरकार बनाने में कामयाब रही. आज प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष मुद्दाहीन होकर कमजोर पड़ गया है. जो केन्द्र सरकार का विरोध कर भी रहे थे, वे अपनी स्थिति को नए सिरे से मजबूत करने को विवश हो गए हैं.

प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव ऐसा है कि रैलियों में कही गई उनकी बातें लोगों पर इस कदर प्रभाव छोड़ती हैं कि उनमें से तमाम चलन में आ जाती हैं. सबका साथ-सबका विकास, अबकी बार मोदी सरकार, देश का चैकीदार, न खाऊंगा न खाने दूंगा जैसी बातें आए दिन लोग बोलते रहते हैं. नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता ने पिछले चार वर्षों में भारत की सीमा लांघ विदेशों में भी अपना असर दिखाया है.

किसने कल्पना की थी कि भारतीय राजनीति के क्षितिज पर एक अज्ञात व्यक्ति किसी चमकते नक्षत्र की भांति अचानक उभरेगा और चारों ओर उसका आभामंडल छा जाएगा. नरेंद्र मोदी की खूबी यह है कि वो अपने आलोचकों को अपनी विफलताओं को उजागर करने का मौका ही नहीं देते. अगर हम 2014 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2014 का लोकसभा चुनाव 'मोदी लहर' के नाम रहा और भाजपा ने अप्रत्याशित बहुमत के साथ केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई.

आज चार वर्षों के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी की सरकार अपने वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है. कुछ वादे पूरे हो चुके हैं, कुछ पर काम जारी है. इस दौरान नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि वृद्धि ही हुई है; यह बात अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सर्वेक्षणों में भी उभरकर आई है. दरअसल मोदी सरकार की नीति और नीयत दोनों ठीक हैं, इसलिए जनता का उसपर विश्वास बरक़रार है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

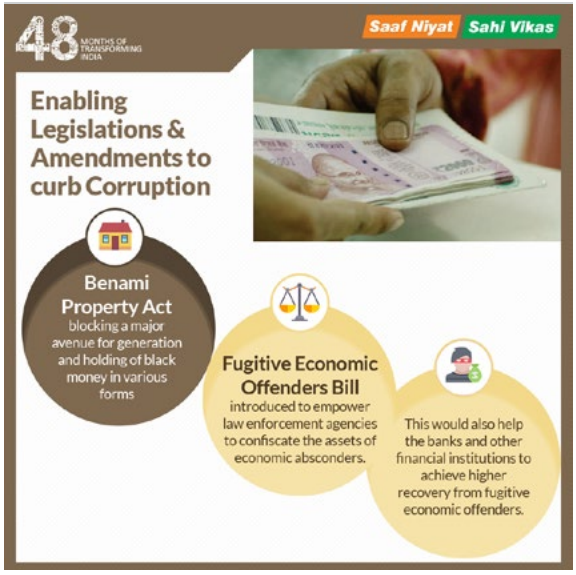

आर्थिक मजबूती, पारदर्शी शासन और कल्याणकारी नीतियों के चार वर्ष!

सतीश सिंह

विगत चार सालों में मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये अनेक कदम उठाये हैं. देखा जाये तो मोदी सरकार द्वारा किये गये विकासात्मक कार्यों की एक लंबी फेहरिस्त है. नवंबर, 2016 में विमुद्रीकरण करने का निर्णय लेना मोदी सरकार द्वारा उठाया गया एक साहसिक कदम था. इस निर्णय से नकसलवाद, आतंकवाद, कालेधन एवं कर चोरी पर रोक तो लगी ही, साथ ही डिजिटलीकरण को भी बढ़ावा मिला. इसके बाद सब्जी वाले, खोमचे वाले, चाय वाले आदि भी डिजिटल लेनदेन करने लगे. इतना ही नहीं बड़े-बुजुर्ग और ग्रामीण महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर डिजिटल लेनदेन में हिस्सा लिया.

जीएसटी से अर्थव्यवस्था को मजबूती

अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिये विमुद्रीकरण के तुरंत बाद जीएसटी को लागू किया गया. यह एक सशक्त अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है. जीएसटी के तहत अलग-अलग कर की बजाय एक कर का प्रावधान किया गया. इससे विनिर्माण लागत में कमी आई. उपभोक्ताओं को आज देश भर में किसी भी सामान या सेवा का एक शुल्क अदा करना पड़ रहा है. टीवी, गाड़ी, फ्रिज एक ही कीमत पर मुंबई, दिल्ली, पटना, भोपाल आदि शहरों में उपभोक्ताओं को मिल रहा है.

इससे कर चोरी की वारदातें एवं कर विवाद के मामले कम हो रहे हैं. टैक्स वसूली की लागत में भी उल्लेखनीय कमी आई है. रोजगार सृजन में वृद्धि, चाइनीज उत्पादों की बिक्री में कमी, जरूरी चीजों पर कर कम होने एवं विलासिता की वस्तुएं महँगी होने से सरकार व आम लोगों दोनों को फायदा हो रहा है.

एक अनुमान के मुताबिक अप्रत्यक्ष कर की इस नई व्यवस्था से अर्थव्यवस्था को 60 लाख करोड़ रुपये का फायदा होने का अनुमान है, जिससे सरकार रोजगार सृजन, आधारभूत संरचना का विकास, औद्योगिक विकास को गति, अर्थव्यवस्था को मजबूत आदि करने में समर्थ हो सकेगी. इससे लाजिस्टिक लागत में भी कमी आयेगी. इस नई कर प्रणाली से देश के विकास दर में लगभग दो प्रतिशत तक का इजाफा

निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित, प्रतिस्पर्धा, उद्यमिता, सरकारी व्यय, राजस्व आदि पर भ्रष्टाचार का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. वर्ष 2011 से वर्ष 2016 के दौरान भारत, ब्रिटेन, पुर्तगाल एवं इटली जैसे देश भ्रष्टाचार की धारणा सूचकांक (प्रति वर्ष पारदर्शिता इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित) में समग्र रूप से श्रेणी उन्नयन करने में सफल रहे हैं. दूसरी तरफ वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट के दौर में भी भारत सकारात्मक जीडीपी दर हासिल करने में सफल रहा है.

होने का अनुमान है.

भ्रष्टाचार में कमी

भ्रष्टाचार को विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा माना जा सकता है. बढ़ते वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्तीय लेनदेन में भ्रष्टाचार की गूँज साफ तौर पर सुनाई देती है. आज कोई भी ऐसा देश नहीं है, जो अपने यहाँ इसकी उपस्थिति से इंकार कर सके. देखा गया है कि भ्रष्टाचार का प्रतिकूल प्रभाव निर्णय लेने की क्षमता और प्राथमिकताओं के चयन पर भी पड़ता है.

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा वर्ष 2016 में प्राप्त कुल शिकायतों में से बाहरी शिकायतें केवल 0.17% ही थीं, जो इस बात का संकेत है कि पहले की तुलना में प्रशासन ज्यादा साफ-सुथरा हुआ है. ई-निविदा, ई-खरीद, रिवर्स नीलामी आदि कार्यों के नवीन प्रौद्योगिकी के जरिये होने से शासन एवं उसकी कार्यविधियों में पारदर्शिता आई है.

भारत वर्ष 2011 के 95 वें श्रेणी में सुधार करते हुए वर्ष 2016 में 79 वें स्थान पर आ गया. भारत में भ्रष्टाचार के स्तर में सुधार आने से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवाह में भी तेजी आई है. आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के प्रति विदेशी निवेशकों का भरोसा पहले की तुलना में बढ़ा है. भारत में शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह पिछले छह सालों यथा, वित्त वर्ष 2012 के 21.9 यूएस बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2017 में 35.9 यूएस बिलियन डॉलर हो गया, जो प्रतिशत में 64 है.

सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था

भारत पिछले तीन सालों से सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है. मुद्रास्फीति वर्ष 2014 से लगातार नीचे आ रही है और चालू वित्त वर्ष में भी यह चार प्रतिशत से ऊपर नहीं जायेगी. इस वित्त वर्ष में चालू खाते का घाटा दो प्रतिशत से कम होगा और विदेशी मुद्रा भंडार 400 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज में सुधार लाने के लिए सरकार ने "इंद्रधनुष" नाम से एक सात आयामी योजना शुरू की है, जिसमें नियुक्तियां, बोर्ड ऑफ ब्यूरो, पूँजीकरण, तनावमुक्त माहौल का सृजन, सशक्तिकरण, जवाबदेही के ढांचे का निर्माण एवं सुशासन जैसे सुधारात्मक पहल शामिल हैं. इसके तहत सरकार4 साल की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूँजी मुहैया करायेगी.

राजकोषीय घाटे को चालू वित्त वर्ष में जीडीपी के 3.2 प्रतिशत के लक्ष्य के दायरे में रखने के लिये लगातार कोशिश कर रही है. औद्योगिक एवं कारोबारी गतिविधियों में तेजी लाने के लिये सरकार सरकारी खर्च में इजाफा कर रही है. केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों ने 3.85 लाख करोड़ रुपये के उनके व्यय

लक्ष्य से 1.37 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च किये हैं. अगले पांच साल के दौरान 83,677 किलोमीटर सड़क निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है.

भारतीय रिजर्व बैंक और कुछअन्य एजेंसियों के अनुसार बेसल III के कार्यान्वयन के बाद बैंकिंग क्षेत्र को लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है. लिहाजा, सरकार बैंकिंग क्षेत्र में 2.11 लाख करोड़ रूपये का पुनर्पूंजीकरण कर रही है, जिसमें बजट के माध्यम से बैंकों को 18,139 करोड़ रूपये दिया जायेगा. 1.35 लाख करोड़ रूपये का पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड जारी किया जायेगा और बची हुई राशि की व्यवस्था बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी को कम करके एवं बाजार से जुटाया जायेगा, ताकि बैंक वैश्विक पूंजी पर्याप्तता एवं बासेल तृतीय के मापदण्डों का पूरी तरह से अनुपालन कर सकें.

अन्य विकासपरक और लोक कल्याणकारी नीतियां

देश में से अंधेरा भगाने के लिये अक्षय ऊर्जा के दोहन के लिये प्रयास किये जा रहे हैं. अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र को व्यापक और प्रभावी बनाने के लिए "नवीन एवं अक्षय ऊर्जा" के नाम से एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया है. भारत विश्व का पहला देश है, जहाँ अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए एक अलग मंत्रालय है. बजट में अक्षय ऊर्जा की क्षमता को 2022 तक 1,75,000 मेगावाट बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है.1,75,000मेगावाट में सौर ऊर्जा का हिस्सा 1,00,000 मेगावाट, पवन ऊर्जा का हिस्सा 60,000 मेगावाट, जैव ईंधन का हिस्सा 10,000 मेगावाट और जल ऊर्जा का हिस्सा 5,000 मेगावाट रहेगा.

सरकार ने वित्त वर्ष, 2019 के बजट में "आयुष्मान भारत" कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना नाम से एक नई योजना की घोषणा की है. इसके अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रस्ताव है. इस योजना के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवार (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) लाभान्वित होंगे और माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर इन्हें प्रति परिवार 5 लाख रूपये तक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जायेगा. प्रस्तावित योजना दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य कार्यक्रम है.

एक लंबे समय से ऑनलाइन सामान बेचने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा खराब या नकली उत्पाद बेचने पर उन्हें ग्राहकों को पैसे वापिस लौटाने के लिये मजबूर करने वाले कानून बनाने की माँग की जा रही थी. इसी क्रम में ग्राहकों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने ई-कॉमर्स नीति बनाने का फैसला किया है. इस नीति का मसौदा 6 महीनों के अंदर लागू किया जायेगा. सरकार चाहती है कि नई नीति में ई-कॉमर्स कारोबार और ग्राहकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाये.

डाटा प्राइवेसी, कराधान, ऑनलाइन कारोबार से जुड़े तकनीकी पहलूओं, जैसेप्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सर्वर को देश में ही रखने और कनेक्टिविटी आदि को इस नीति में जगह दी जायेगी. नीति बनाने के लिये एक समिति का गठन किया गया है, जो 5 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा. तदुपरांत, एक महीने के अंदर समिति की सिफ़ारिशों को अमलीजामा पहनाया जायेगा.

कहा जा सकता है कि मोदी सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक सरोकार दोनों ही मोर्चों को मजबूत करने का काम किया है. वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उज्ज्वला योजना, मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के लिये ज्यादा राशि का आवंटन आदि के माध्यम से भी आम जनता को सशक्त बनाने का काम कर रही है.

(लेखक भारतीय स्टेट बैंक के कॉरपोरेट केंद्र मुंबई के आर्थिक अनुसंधान विभाग में कार्यरत हैं. प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं.)

चार सालों में सुशासन और विकास के हर मोर्चे पर कांग्रेस से बेहतर साबित हुई है मोदी सरकार!

अभय सिंह

2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपानीत राजग की सरकार सत्ता में आई. आजादी के इतने वर्षों बाद पहली बार गैर-कांग्रेसी सरकार को अकेले दम पर बहुमत मिला. नरेन्द्र मोदी के करिश्माई चेहरे के आगे विपक्ष ढेर हो गया. जनता ने मोदी को दिल खोलकर अपना समर्थन दिया. इसका मुख्य कारण था कांग्रेसनीत संप्रग सरकार की कुनीतियाँ. कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुँच गया था और हर तरफ सिर्फ घोटालों, लालफीताशाही, स्कैम्स की गूंज थी.

जनता इस निराशावादी माहौल को आशावादी रूप में पलटने को तैयार थी. इसके बाद मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र को एक उम्मीद मिली, यह उम्मीद थी परिवर्तन और विकास की. लेकिन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना कतई सरल नहीं था. लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह जिम्मा उठाया और आज जब सरकार अपने चार वर्ष का उत्सव मना रही है, तो यह ना सिर्फ सरकार बल्कि देश की जनता के लिए भी विकास और सुशासन के चार वर्षों का उत्सव है.

इस सरकार ने जब कार्य करना प्रारंभ किया, उस दिन से ही इसने समग्र विकास की नींव रखी. सरकार निरंतर गरीब, पीड़ित और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कार्य करती रही, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जनधन, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मुद्रा, स्टार्टअप इंडिया, अटल पेंशन आदि अनेक योजनाएं हैं. इन योजनाओं के आलोक में वर्तमान सरकार की विकास और लोक कल्याण की नीयत साफ दिखाई देती है.

यह विडंबना है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम देश के गरीब तबके को बैंकिंग सिस्टम में नहीं ला पाए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जनधन योजना से 31.52 करोड़ खाते खोले गए. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2014-17 के बीच पूरे विश्व में जितने नए बैंक खाते खुले उसमें अकेले भारत का 55 प्रतिशत हिस्सा रहा है. आलम यह है कि अब लगभग 80 फीसद वयस्कों के पास अपना बैंक अकाउंट है. इससे डिजिटल लेनदेन में भी इजाफा हुआ है.

इतना ही नहीं, सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर(डीबीटी) से यह भी सुनिश्चित किया कि अनेक

योजनाओं के लाभार्थियों को बिना बिचौलियों की रुकावट के सीधे अपने खाते में पैसे प्राप्त हो जाएँ. पिछली सरकार के दौरान डीबीटी से सिर्फ 28 योजनाएँ ही जुड़ी थीं, लेकिन अब 433 योजनायें इससे जुड़ चुकी हैं और इससे देश को 83,000 करोड़ का लाभ हुआ है.

यहाँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जिक्र करना भी समीचीन होगा. उज्ज्वला योजना के जरिये अबतक 3.8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलिंडर दिया गया है. स्पष्ट है, उज्ज्वला के माध्यम से करोड़ों गरीब परिवारों को धुआं रहित जीवन देना का काम हुआ है और योजना की सफलता को देखते हुए सरकार ने अब इसका लक्ष्य 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया है.

देश को स्वच्छ बनाने के साथ-साथ महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान को सुरक्षित करने का कार्य सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के जरिये किया है. योजना के तहत अबतक 7.25 करोड़ से भी अधिक शौचालयों का निर्माण कार्य हुआ है और 3.6 लाख से ज्यादा गाँव एवं 17 से अधिक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुके हैं. स्वच्छता अभियान की सफलता का अंदाज़ा इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि 2014 में जहाँ स्वच्छता कवरेज 35 प्रतिशत था, वह अब बढ़कर 85 प्रतिशत पर पहुँच गया है.

संप्रग सरकार लगातार यह कहते हुए नहीं थकती है कि 'आधार' हम लेकर आये. लेकिन जब मोदी सरकार ने आधार का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल कर बिचौलियों को ख़त्म करने का काम किया है, तो फिर आखिर परेशानी किस बात की. अगर आधार और डीबीटी से देश का पैसा बच रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है ?

आजादी के बाद लगभग साठ वर्षों तक सत्ता में रहते हुए भी कांग्रेस देश को अँधेरे से मुक्ति नहीं दिला पाई, लेकिन मोदी सरकार ने मात्र चार साल में यह काम कर दिखाया है.2014 से पहले जो 18,500 गाँव अँधेरे में थे, वहाँ अब स्थिति बदल चुकी है. अब देश में सभी गांवों में बिजली आ चुकी है और सरकार हर घर तक बिजली पहुँचाने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है. इस कार्य के लिए विश्व बैंक ने भी मोदी सरकार की सराहना की है.

देश में पहली बार ऐसा नेतृत्व है, जो लोक-लुभावन नीतियों की बजाय जनता के हित में कड़े फैसले लेने में भी नहीं हिचकता. नोटबंदी और जीएसटी का फैसला इसी का उदाहरण है. नोटबंदी के बाद जहाँ देश में आयकरदाता 81 फीसद बढ़े, तो जीएसटी से पहले देश में 65 लाख पंजीकृत करदाता थे, जिनकी संख्या अब 1 करोड़ से अधिक हो गयी है. उसी तरह 2013-14 के मुकाबले 2017-18 में आयकर रिटर्न की संख्या 6.84 करोड़ हुई जो कि 80.5% अधिक है.

कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार, कालाधन, घोटालों का वर्चस्व था; वहीं मोदी सरकार ने सत्ता में आने के साथ ही कालेधन, भ्रष्टाचार पर प्रहार शुरू किया. इस सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही विशेष जाँच दल का गठन किया, स्विट्ज़रलैंड के साथ कालेधन से जुड़ी सूचनाएं साझा करने के लिए समझौता; कालाधन तथा कर अधिरोपण कानून-2015 को लागू करना; करीब तीन लाख कंपनियों पर कार्यवाही; बेनामी संपत्ति अधिनियम से कालेधन पर लगाम लगाना; आर्थिक भगोड़ों की संपत्ति जब्त करने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लाना जिससे बैंकों को आर्थिक अपराधियों पर कार्यवाही करने में आसानी होगी; आदि ये सरकार के वो कार्य हैं, जो भ्रष्टाचार और कालेधन के प्रति उसकी 'जीरो टॉलरेंस' की नीति को दिखाते हैं.

केंद्र की मोदी सरकार किसानों की समृद्धि के लिए कृतसंकल्पित और देश के किसान की आय को 2022

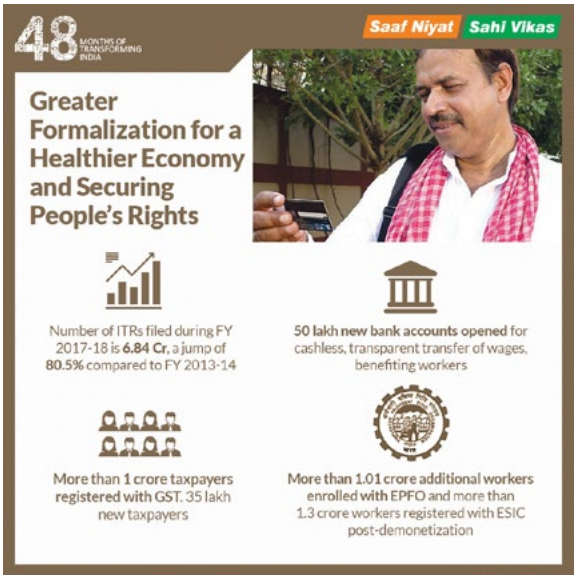

तक दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है. योजना के तहत अबतक 4.05 करोड़ किसान कवर किये जा चुके हैं और 379.06 लाख हेक्टेयर भूमि का बीमा किया जा चुका है.इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत 2014-18 के दौरान 5460.12 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई जो 2010-14 में 4698.65 करोड़ रूपए से 16.21 प्रतिशत अधिक है.

इसके अलावा ई-नाम योजना के जरिये 585 नियमित मंडियों को जोड़ने का काम हुआ है. चाहे मृदा स्वस्थ कार्ड हो या डीडी किसान चैनल हो, हर तरह से सरकार किसानों की बेहतरी के लिए कार्य कर रही है. महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी सरकार ने बेहतर काम किया है. मिशन 'इन्द्रधनुष' से 80 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया है.'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' से अबतक लगभग 104 जिलों में लड़का-लड़की अनुपात में सुधार हुआ है.

रोजगार के विषय पर बात करें तो आज भारत में 65% से अधिक की आबादी युवाओं की है, जिन्हें रोजगार देना महत्वपूर्ण हो जाता है. इसलिए मोदी सरकार ने ना सिर्फ रोजगार बल्कि स्वरोजगार पर भी बल दिया है. सरकार जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर के तौर पर युवाओं को देखती है. इसके लिए सरकार ने रोजगार सृजन के लिए कई कार्य प्रारंभ किये हैं, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक अवसर प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे का नए सिरे से निर्माण, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया से स्वरोजगार का कार्य प्रगति पर है.

केंद्र सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए 'आयुष्मान भारत' जो कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा पहल है, लाई है. इसमें 50 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रूपए तक का स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा. सरकार गरीबों के लिए समर्पित रूप से कार्य कर रही है. प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिये गरीब से गरीब परिवार को 2022 तक घर देने का लक्ष्य है और पिछले साढ़े तीन वर्षों में ग्रामीण और शहरी इलाकों में करीब 1 करोड़ मकानों का निर्माण किया गया है. इसके अतिरिक्त 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' से प्रत्येक गाँव को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है और अब ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी वर्ष 2014 के 56 प्रतिशत से बढ़कर 82 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच चुकी है.

अगर हम विकास की बात करें, तो रेलवे को इससे अलग नहीं रखा जा सकता है और इसमें भी दुर्घटनाओं का प्रतिशत अगर कम होता है, तो निश्चित रूप से सरकार की दशा व दिशा सही है. आंकड़ों पर जाएँ तो 2013-14 के 118 के मुकाबले 2017-18 में 73 पर आ गयी है जो कि 62 प्रतिशत कम है. लेकिन सरकार अब भी इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है, जिससे दुर्घटनाएँ बिलकुल न हों. भारतीय रेलवे में एक नया आयम तब स्थापित हुआ जब मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को स्वीकृति मिली और इस पर कार्य भी तेजी से हो रहा है. जिसके बाद 8 घंटे से कम होकर मुंबई-अहमदाबाद की दुरी सिर्फ 2 घंटे में पूरी की जा सकेगी.

बहरहाल, चार वर्ष के कार्यकाल के बाद भी जनता का अटूट विश्वास मोदी सरकार पर बना हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी अब भी जनता की पहली पसंद बने हुए हैं. इन चार सालों में सुशासन और विकास के किसी भी मोर्चे पर अगर अवलोकन करें तो मोदी सरकार कांग्रेसनीत संप्रग सरकार से बेहतर साबित होती है. सरकार निरंतर 'सबका साथ सबका विकास' के अपने मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है और देश के समग्र विकास के लिए प्रयासरत है.

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं. प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं.)

सुरक्षा, विकास और राष्ट्रीय गौरव के चार वर्ष !

नवोदित सक्तावत

केंद्र में भाजपा की सरकार के चार वर्ष पूरेहो चुके हैं.16 मई, 2014 की तारीख को लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए थे और साफ़ हो गया था कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त करते हुए भाजपा को विशाल बहुमत दे दिया है. दूसरे अर्थों में इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि जनता की पूरे मन से भाजपा को ही सत्ताय में लाने की उत्करट कामना थी, जो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के रूप में परिणित हुई. आज इस घटना के चार वर्षों बाद भाजपा ने उन सारे मतदाताओं का धन्यपवाद अपनी उपलब्धियों एवं कार्यों के ज़रिये कर दिया है, जिन्होंने पूरे विश्वावस के साथ भाजपा को अपना वोट दिया था. निश्चित ही इस दौरान सरकार की उपलब्धियों की संख्या अधिक है, इसलिए उन्हें गिनाना संभव नहीं है, लेकिन मूल स्वरर पर जरूर बात की जा सकती है.मूल स्वनर यही है कि आज पूरे विश्वन में भारत की छवि एक उन्नभत और समर्थ राष्ट्रत की बन गई है. इसी के चलते विश्वव के बड़े और शक्तिशाली देश भी भारत के प्रति सम्मारन एवं सहयोग की भावना प्रकट कर रहे हैं. असल में यह अपने आप में एक बड़ा मापदंड है कि देश के बाहर अंतरराष्ट्री य मंच पर आपके देश की क्याि स्थिति है. देश के हर नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत को अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में ला खड़ा किया है. इन चार सालों में विश्व भर में भारत के गौरव में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है.

इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी को 2014 में देश जिस हालत में मिला था, उन्होंनि उसे अपने मात्र चार वर्षों के कार्यकाल में ही वहाँ से कहीं आगे ले जाकर दिखा दिया है. सफलता की बातें और सफलता को साझा करना सभी को अच्छी लगता है, लेकिन संघर्ष पर कम बातें होती हैं.2014 में देश की हालत हर तरह से डांवाडोल थी. हमें यह भी जानना चाहिये कि आखिर क्यों पूरे देश के मन में तत्काालीन कांग्रेस सरकार के प्रति गुस्सेच का उबाल था. आखिर कौन सी वजहें थीं, जिनके चलते मतदाताओं ने एकजुट होकर कांग्रेस को सत्ताा से उखाड़ फेंका और भाजपा की ताजपोशी की.

कांग्रेस की सरकार में नित नए घोटाले सामने आते थे. ऐसा लगता था मानो कांग्रेस के मंत्री घोटाले के सिवाय कुछ

करना जानते ही नहीं हों.2जी घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला आदि ऐसे बड़े घोटाले थे, जिन्होंने कांग्रेस का तो नुकसान किया ही, देश को भी बहुत पीछे ला खड़ा किया. आज 4 साल हो गए हैं और भाजपा सरकार पर एक भी घोटाले का आरोप तक नहीं है. वही सरकारी मशीनरी है, वही नौकरशाह हैं, फिर यह बदलाव कैसे हो गया ? जवाब एक ही है-नेतृत्वथ.

तब देश का नेतृत्व कांग्रेस जैसे दल के हाथ में था, जिसमें प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह थे, पर कार्य सत्ता का नेहरू-गाँधी परिवार के पास ही था. अब शासन भाजपा के हाथ में है और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का मजबूत नेतृत्व है. आपको याद होगा कि जिस दिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उन्होंहने राष्ट्रय से आहवान किया था कि अब आप चिंता छोड़ दीजिये. अच्छेथ दिनों का जुमला महज वाक्यष-विन्याास अथवा शब्दोंि की लफ्फाजी भर नहीं है, वह गहरे अर्थों में एक कार्य-संस्कृ ति है. वह एक आचरण है, एक शैली है, एक विचारधारा है. अच्छेद दिनों का जिक्र करने का अर्थ यही होता है कि अभी तक निश्चित ही अच्छे् दिन नहीं थे, इसलिए अब आने वाला समय अच्छान होगा. अच्छेन से आशय किसी कल्पदनालोक से नहीं वरन धरातल से है.

देश में हर मोर्चे पर बदलाव आया है. जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, फसल बीमा योजना, सौभाग्य योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, आयुष्मान योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्री य सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और तत्का्लीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की सूझबूझ और साहस के बूते यह हो पाया. पहले कश्मीकर घाटी में आए दिन आतंकवादियों के हमले की खबरें आती थीं, लेकिन अब भारतीय सेना द्वारा आतंकियों के मार गिराए जाने की खबरें आती हैं. बुरहान वानी के पूरे दल का हाल ही में सफाया हो चुका है. आतंक विरोधी ऑपरेशन के चलते भारतीय सेना लगातार आतंकवादियों को खदेड़ने में सफल रही है. कांग्रेस की सरकार के समय ऐसा नहीं था. भाजपा के आने के बाद आतंकियों के पाँव उखड़ने लगे हैं.

आदि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की धारा को पहुँचाने वाली अनेक योजनाओं सहित राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति आदि हर बिंदु पर बड़ा बदलाव देखा जा सकता है. राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव इससे संबंधित मामलों में पाएंगे. पहले आए दिन देश के किसी ना किसी शहर में बम विस्फोसट की खबरें आया करती थीं और ऐसा लगता था मानो राष्ट्रे के नागरिक हर पल मौत, आतंक, खौफ के साये में जीने को विवश हैं. आज हालात बदल गए हैं. भारतीय सेना पहले से बहुत अधिक सशक्त, और आत्मयविश्वा स से भरी नजर आने लगी है.

पिछले 4 साल में सीमा पर, सैन्यव इलाकों में जरूर आतंकी हमले हुए और सुरक्षाबलों ने उनका मुंहतोड़ जवाब भी दिया, लेकिन आतंकवादी राज्योंि की सीमा पार करके शहरों में प्रवेश नहीं पा सके. सीमा की भी बात करें तो उड़ी जैसे नृशंस हमले का प्रतिशोध सर्जिकल स्ट्रा इक जैसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम देकर लिया गया.

यदि हम अर्थव्यखवस्थो की बात करें तो हर छोटे से छोटे व्याक्ति की परचेजिंग पॉवर यानी क्रय क्षमता में पहले से इजाफा हुआ है. गांवों में भी अब स्मा र्ट उपभोक्तार पाए जाने लगे हैं. डिजिटल क्रांति का ऐसा सूत्रपात हुआ है कि बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन कारोबार, लेनदेन, भुगतान सफलतापूर्वक कर रहे हैं.

इंटरनेट के इस शिखर युग में युवाओं ने स्टौर्टअप्स खोले और स्वलयं की कमाई के अलावा दूसरों को भी रोजगार देने की दिशा में बढ़ रहे हैं. ये वही लोग हैं, जो पहले किसी स्थोपित संस्थागनों या कारोबारियों पर ही आश्रित थे, लेकिन अब इनके लिए स्वंरोजगार की संभावनाएं अपने वृहद परिप्रेक्ष्यो में उभरकर सामने आई हैं. मोबाइल फोन में बैलेंस डालने जैसी रोजमर्रा की जरूरत के लिए भी पहले उपभोक्तो को बाजार पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अब वह घर बैठे खुद अपने मोबाइल से बैलेंस डाल सकता है. डिजिटल क्रांति का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता.

नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता केवल भारत में ही सीमित नहीं है, वे अब एक वैश्विक राजनेता बन चुके हैं. इजराइल जैसे राष्ट्रं ने भी भारत की ओर दोस्तीअ का हाथ बढ़ाया और वहां के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की. यह सब पहले सहज नहीं हुआ करता था. रूस और अमेरिका जैसे परस्पर विरोधी देशों से भी संबंधों का शानदार संतुलन मोदी ने स्थापित किया है.

प्रायः किसी भी सरकार या नेता के कार्यकाल के दौरान उसकी लोकप्रियता में कमी ही देखने को मिलती है, मगर नरेंद्र मोदी इस मामले में अपवाद हैं. आए दिन कई प्रकार के सर्वे में उनकी लोकप्रियता के प्रतिमानों की सूचनाएं भरी पड़ी रहती हैं. सोशल मीडिया के प्लेरटफार्म से लेकर गणराज्योां तक मोदी प्रभावशाली व्यडक्तियों की सूची में दर्ज हैं. देश में उनकी लोकप्रियता में वृद्धि ही देखने को मिल रही है.

अब बात करते हैं विपक्ष की. कहने की जरूरत नहीं है कि इन बीते 4 वर्षों में कांग्रेस एक विपक्ष के तौर पर बुरी तरह असफल रही है. वह ठीक से विपक्ष का काम भी नहीं कर पाई. ठीक से काम करना आता तो हाथ से सत्ताह ही क्योंठ जाती. असल में विपक्ष का दल होना साधारण बात नहीं है, इसमें भी एक योग्योता की दरकार होती है. विपक्ष के भीतर भावी पक्ष बनने की संभावना होती है. इसके लिए दूरदर्शिता और योग्यरता चाहिये. एक विपक्ष के तौर पर भाजपा पूरी तरह सक्रिय और सफल रही थी, तभी 2014 में वह सत्ता में आ पाई. लेकिन, कांग्रेस तो सत्ता् से हटाए जाने के बाद विपक्ष के रूप में भी लचर, कमजोर, सतही, असफल और कुंद रही है.

विपक्ष के रूप में कांग्रेस ने नकारात्मक राजनीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया है. कांग्रेस के पास विरोध करने के लिए कोई ठोस या रचनात्मिक मुद्दा नहीं था, तो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने शालीनता की हदें पार करते हुए घटिया भाषा का उपयोग किया और प्रधानमंत्री सहित अन्य वरिष्ठं नेताओं पर व्यषक्तिगत आक्षेप किए, जिसका प्रतिफल उसे 2014 के बाद हुए अनेक राज्यों के विधानसभा चुनावों में जनता ने दिया भी. मगर, फिर भी कांग्रेस को होश आता नहीं दिख रहा.

कांग्रेस ने अक्स.र गलत ढंग से हावी होने की नाकाम कोशिशें की, लेकिन जनता की आंखें खुल चुकी हैं. अब अवाम देख-समझ रहा है कि मौजूदा सरकार ने 4 सालों में काम ही काम किया है. नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिना भ्रष्टा चार के एक आरोप के बेदाग़ ढंग से शासन चलाए जाने की मिसाल कायम की है. निश्चित ही 2019 के चुनाव में भी देश की जनता इसी प्रकार भाजपा पर विश्वाकस बनाए रखेगी और नरेंद्र मोदी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनकर सामने आएंगे ताकि वे अपनी देश सेवा का अभियान जारी रख सकें और भारत का प्रगति रथ अविरत गति से यूं ही आगे बढ़ता रहे.

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं. ये उनके निजी विचार हैं.)

'इन एक्सप्रेसवे पर फर्राटे भरते हुए आप मोदी सरकार के आधुनिक भारत से रूबरू हो सकते हैं'

credit : www.ndtv.com

अजेन्द्र अजय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मई को जो दो दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे व ईस्टर्न पेरिफेरल (पूर्वी परिधीय) एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किए, उनकी गिनती देश में अब तक निर्मित एक्सप्रेसवे की भांति नहीं की जा सकती है. यह दोनों एक्सप्रेसवे स्मार्ट और हाईटेक सुविधाओं से युक्त हमारी इंजीनियरिंग की मिसाल भी हैं. इन एक्सप्रेसवे पर फर्राटे भरते हुए देश के नागरिक मोदी सरकार के आधुनिक भारत की मजबूत नींव से रूबरू हो सकते हैं और यह भी गर्व कर सकते हैं कि हम तकनीकी के मामले में दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं हैं.

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे लगभग 82 किलोमीटर लंबा होगा. प्रधानमंत्री मोदी ने इसके प्रथम चरण में दिल्ली स्थित निजामुद्दीन पुल से उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक करीब 9 किलोमीटर लंबे मार्ग का उद्घाटन किया. यह देश का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे है. शुरू के 27 किलोमीटर तक यह 14 लेन का रहेगा. शेष 6 लेन का. प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर, 2015 में इसका शिलान्यास किया था. लगभग 842 करोड़ की लागत से निर्मित प्रथम चरण का कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ. इसके निर्माण का लक्ष्य 30 माह रखा गया था. इसके विपरीत मात्र 18 माह में निर्माण कार्य पूरा हो गया.

यह पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिसमें दिल्ली से डासना के बीच 28 किलोमीटर के खंड पर बाइसिकिल ट्रैक भी होगा. केंद्र सरकार ने इस पूरे एक्सप्रेसवे के

निर्माण के लिए मार्च 2019 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके निर्माण के बाद दिल्ली से मेरठ तक की यात्रा मात्र 45 मिनट में पूरी की जा सकेगी. इसका लाभ पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड को भी मिलेगा. इसके अलावा प्रतिवर्ष उत्तराखंड की यात्रा पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं व पर्यटकों के समय के साथ पैसों की बचत भी होगी.

दिल्ली को बाईपास कर हरियाणा और यूपी के शहरों को जोड़ने वाला 135 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न पेरिफेरल देश का सबसे तेज एक्सप्रेसवे है. अभी तक यमुना एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वाहन चलाने की अनुमति थी. मगर अब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वाहन दौड़ सकेंगे. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जाम व प्रदूषण को काफी हद तक दूर करने की क्षमता रखने वाला यह एक्सप्रेसवे अपनी बनावट, निर्माण शैली व सुविधाओं के लिहाज से विश्वस्तरीय एक्सप्रेसवे की कतार में खड़ा हो गया है.

आधुनिक हाईवे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए वाहनों को स्पीड, ट्रैफिक, दुर्घटना, डायवर्जन आदि के बारे में निर्देशित किया जा सकेगा. एक्सप्रेसवे पर बिजली की व्यवस्था सोलर प्लांट के जरिए की जाएगी. तमाम स्थानों पर हमारे ऐतिहासिक स्थलों के प्रतीक

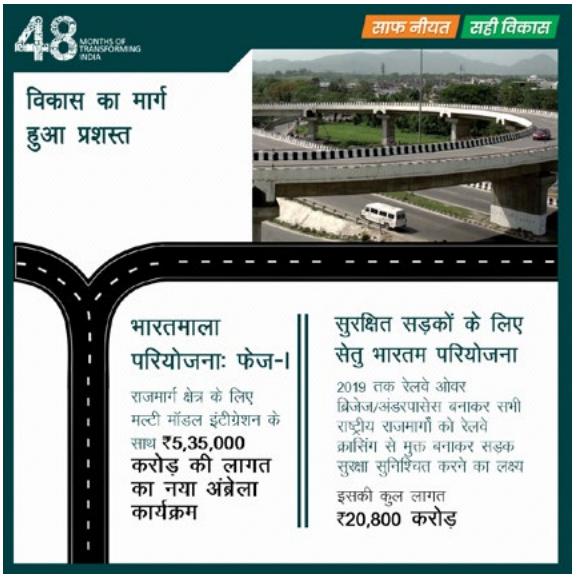

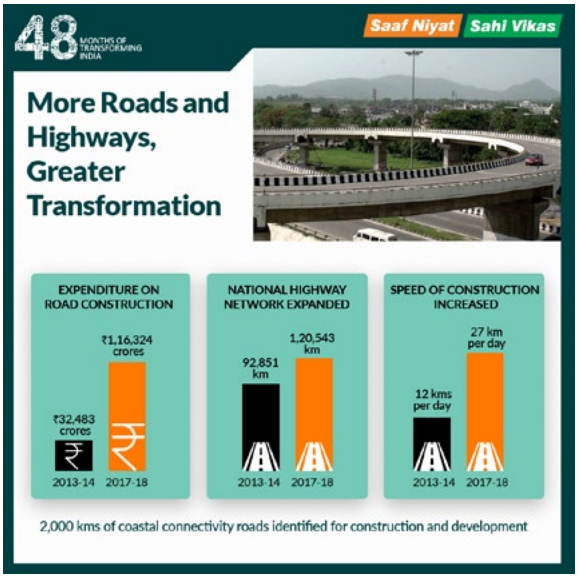

चित्र, लाइटिंग, मोटल, खाने-पीने के स्थान आदि इस एक्सप्रेसवे की यात्रा को यादगार बनाने में सफल साबित होंगे. रेन वाटर हार्वेस्टर के जरिए हाईवे को ग्रीन बेल्ट के रूप में तब्दील किया जाएगा.

11 हजार करोड़ की लागत से तैयार इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास पीएम मोदी ने नवंबर, 2015 में किया था. यह एक्सप्रेसवे भी अपने निर्धारित लक्ष्य से काफी पहले रिकॉर्ड 500 दिन में तैयार हो गया. एक्सप्रेसवे के निर्माण से 4 घंटे की यात्रा अब सवा घंटे में पूरी की जा सकेगी.

आज हम इन उपलब्धियों के लिए यदि मुस्कुरा रहे हैं, तो इसका अवसर उन तमाम इंजीनियरों व श्रमिकों ने हमें प्रदान किया है, जिन्होंने रात-दिन एक कर समय से पहले यह निर्माण कार्य पूरे किए हैं. और इससे भी बढ़कर रही मोदी सरकार की दृढ़-इच्छाशक्ति.

प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया. सरकार ने आधारभूत संरचनाओं के विकास की दिशा में आगे बढ़ते हुए बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बेहतर सड़कों के निर्माण पर अपना फोकस किया. पीएम मोदी के इस मिशन को केंद्रीय सड़क परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पूरे दमखम व कुशलता से धार दी.

वर्ष 2014 में मोदी सरकार के सत्ता संभालते वक्त सड़क परिवहन के क्षेत्र में बड़ी चुनौतियां थीं. व्यापक भ्रष्टाचार के चलते निवेश का माहौल कम था. तमाम सड़क परियोजनाएं विभिन्न विवादों के चलते लंबित पड़ी हुई थीं. मोदी सरकार के गठन के बाद बाधाएं दूर करने के लिए गंभीर प्रयास किए गए. लंबित ठेकों के विवाद निपटाने में सरकार ने तेजी दिखाई. विवादों को न्यायालय में जाने से रोकने के लिए सरकार ने रणनीतिक कुशलता का परिचय दिया. भूमि अधिग्रहण के मामले में पेंचीदगियों को दूर किया गया. किसानों को भूमि का मुआवजा बाजार भाव से अधिक दिया गया.

मोदी सरकार ने शुरू में सड़क निर्माण के लिए निर्माण, संचालन और स्थानांतरण (बीओटी) के इकोनॉमी मोड का इस्तेमाल किया. मगर इसके अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने पर इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति एवं निर्माण (ईपीसी) का तरीका अपनाया. इसमें सरकार धन की व्यवस्था करती है. निजी कंपनियां एक निश्चित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने का अनुबंध करती हैं.

मोदी सरकार ने सड़क निर्माण से जुड़े नीति-निर्माताओं के मार्गदर्शन के लिए देश में पहली बार 'राजमार्ग क्षमता नियम पुस्तिका' जारी की. राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोग्राम को लागू किया. इसका मकसद परियोजनाओं की लागत में कमी के साथ-साथ पर्यावरण अनुकूलन, नई प्रौद्योगिकी, सामग्री व उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना था.

देश में पहली बार भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस) लांच की गई. इस प्रणाली के लांच होने के बाद पुलों का डाटा बैंक बनाया गया है. इसमें पुलों का पूरा लेखा-जोखा, स्थिति, ढांचा, मरम्मत आदि के बारे में पूरी जानकारी रहेगी. मोदी सरकार सड़क निर्माण में लगे पेशेवरों, श्रमबल आदि के कौशल में वृद्धि के लिए भी व्यापक कार्यक्रम चलाने को प्रयासरत है.

मोदी सरकार के इन प्रयासों का परिणाम अब दिखने लगा है. यूपीए सरकार के समय में जहां प्रतिदिन 11 से 12 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा था, वहां आज आंकड़ा 27 किलोमीटर प्रतिदिन पहुंच गया है. केंद्र सरकार ने वर्ष 2017-18 के मुकाबले वर्ष 2018-19 में 45 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अकेले वित्तीय वर्ष 2017-18 में 9829 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में एक लाख सोलह हजार करोड़ रुपए खर्च किए. सरकार ने वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक 5 वर्षों के लिए दीर्घकालीन योजना प्रस्तावित की है. इस दौरान सड़क निर्माण के क्षेत्र में लगभग सात लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई गई है.

केंद्र सरकार का अनुमान है कि वर्ष 2018-22 की अवधि में सड़क निर्माण योजना से 12.5 करोड़ श्रम प्रतिदिन प्रतिवर्ष सृजित होंगे. इनमें एक करोड़ प्रोफेशनल, 3.5 करोड़ कुशल श्रम दिवस और आठ करोड़ अर्द्ध कुशल व अकुशल श्रम दिनों का सृजन हो सकेगा. यानी सड़क निर्माण का कार्य जहां एक ओर आधारभूत ढांचे के निर्माण में कारगर साबित होगा, वहीं रोजगार सृजन की राह का विस्तार करेगा.

(लेखक उत्तराखंड भाजपा के मीडिया संपर्क विभाग के प्रमुख हैं.)

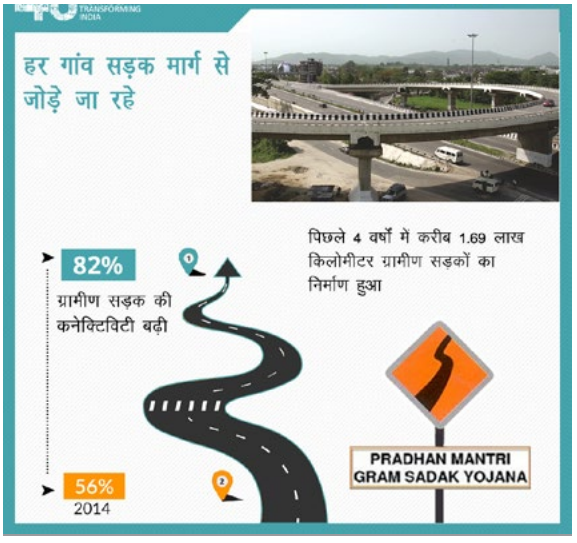

'इसे मोदी इफेक्ट ही कहेंगे कि 30 महीने का काम 17 महीने में ही पूरा हो गया'

रमेश कुमार दुबे

प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी को बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं की लेट-लेतीफी और उनकी बढ़ती लागत ने चिंता में डाल दिया. इसे देखते हुए उन्हों ने सांख्यिेकी एवं कार्यक्रम क्रियान्यीन मंत्रालय से रिपोर्ट तलब की. मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भूमि अधिग्रहण संबंधी जटिलताओं और पर्यावरण संबंधी मंजूरी में देरी अर्थात जयंती टैक्सप के कारण देश की परियोजनाएं पिछड़ती जा रही हैं जिससे उनकी लागत भी बढ़ती जा रही है. मंत्रालय ने आकलन करके बताया कि बुनियादी ढांचा संबंधी 273 बड़ी परियोजनाओं में लेट-लतीफी के चलते उनकी लागत में 1.77 लाख करोड़ रूपये का इजाफा हो चुका है.परियोजनाओं में देरी करके मुनाफा कमाने के इस कुचक्र को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूचना–प्रौद्योगिकी का इस्तेइमाल करते हुए उनकी निगरानी को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से संबद्ध किया. नियोजन व निगरानी के लिए जीआईएस व अंतरिक्ष संबंधी चित्रों का उपयोग करने के साथ-साथ विभिन्नव स्तिरों की संख्यास कम करके धनराशि का कारगर प्रवाह सुनिश्चिरत किया गया है.

सामग्री की खरीद, निर्माण और रख-रखाव जैसे चरणों में गुणवत्तान संबंधी कठोर निगरानी की जाने लगी. हर महीने प्रगति कार्यक्रम के जरिए इसकी समीक्षा की जाने लगी. इसका नतीजा यह हुआ कि परियोजनाओं ने रफ्तार पकड़ ली. इसे मोदी सरकार के कार्यकाल में सड़क निर्माण में आई क्रांति के उदाहरण से समझा जा सकता है.

2013-14 में देश में हर साल 4260 किलोमीटर राजमार्गों (हाईवे) का निर्माण हो रहा था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सख्तीं के चलते 2014-15 में 4410 किलोमीटर, 2015-16

में 6061 किलोमीटर और 2016-17 में 8231 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण हुआ.2017-18 में 17055 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के ठेके दिए गए और 9829 किलोमीटर सड़कें बनी.

यदि इसे रोजाना की दृष्टि से देखें तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले देश में जहां हर रोज 11 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण हो रहा था, वहीं अब यह आंकड़ा 30 किलोमीटर प्रतिदिन से ज्या दा हो गया है. मोदी सरकार ने इस अनुपात को 40 किलोमीटर तक पहुंचाने का लक्ष्यि रखा है. इससे स्पकष्टम है कि मोदी सरकार के आने के बाद देश में हाईवे निर्माण ने रफ्तार पकड़ ली.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजमार्गों के साथ-साथ ग्रामीण सड़कों के निर्माण को भी प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि ग्रामीण अर्थव्यजवस्थाथ शहरों से जुड़ सके. सरकार प्रति हेक्टे यर पैदावार बढ़ाने के उपाय करने के साथ-साथ फल, फूल, सब्जीस आदि के लिए प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, कोल्ड7 स्टोलरेज जैसे बुनियादी ढांचे में भारी निवेश कर रही है ताकि कृषि उपजों के कारोबार को बढ़ावा मिले.

प्रधानमंत्री इस बात को अच्छीह तरह जानते हैं, ये निवेश तभी कारगर होंगे जब गांवों को बारहमासी सड़क संपर्क हासिल हो. जहां 2011-14 के दौरान हर रोज औसतन 70 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गईं, वहीं 2014-15 में यह आंकड़ा बढ़कर 100 किलोमीटर हो गया.2016 में तो इसमें अभूतपूर्व तेजी आई और आज हर रोज 139 किलोमीटर सड़क बन रही है.

जो ग्रामीण सड़कें अब तक ठेकेदारों और स्थाहनीय नेताओं के रहमोकरम पर बनती थीं, उनकी गुणवत्ताी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने बहुआयामी उपाय किए जिससे सड़कों की गुणवत्ताी में सुधार हुआ. सड़क से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए "मेरी सड़क" नामक एप शुरू किया गया है. सरकार ने 2019 तक सवा दो लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़क निर्माण का लक्ष्यि रखा है.

परियोजनाओं की लेट-लतीफी के जरिए अपनी तिजोरी भरने वाली ताकतवर लॉबी से टक्कगर लेना इतना आसान काम नहीं था. मोदी सरकार ने इसके लिए कई नीतिगत बदलाव किया. सरकार ने सबसे पहले भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण क्लीयरेंस तथा कोष की कमी जैसी समस्याकओं को दूर किया.

इसके अलावा उपग्रह आधारित सड़क परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली, सड़क निर्माण के लिए कंक्रीट का इस्तेवमाल, इलेक्ट्रा निक टॉल संग्रह, इनमप्रो जैसे सूचना तकनीक संबंधी कदम उठाए गए. इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी और सड़क निर्माण में क्रांति आ गई. इसे कहते हैं, 56 इंच सीने का कमाल. दुर्भाग्यबवश मोदी विरोधियों को यह उपलब्धि.यां दिखाई नहीं दे रही हैं.

(लेखक केन्द्रीय सचिवालय में अधिकारी हैं. प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं.)

‘कांग्रेस बैलगाड़ी की रफ़्तार से योजनाएं लागू करती थी, मोदी बुलेट जैसी तेजी दिखाते हैं’

डॉ दिलीप अग्निहोत्री

कांग्रेस यह कहती रहती है कि मोदी सरकार ने उसकी अनेक योजनाएं को ही आगे बढ़ाया है, लेकिन यह कहने में कोई समझदारी नहीं है. क्योकि जब कांग्रेस अपनी योजनाओं की दुहाई देती है, तो उसकी और नरेंद्र मोदी की कार्यशैली का तुलनात्मक अध्ययन होने लगता है.

तुलना करते ही स्पष्ट हो जाता है कि यदि कांग्रेस बैलगाड़ी की चाल से योजनाएं लागू करके काम शुरू करती थी, तो नरेंद्र मोदी बुलेट जैसी तेजी दिखाते हैं. इतना ही नहीं, कांग्रेस ने लाखों करोड़ रुपये की योजनाएं अधूरी या लंबित छोड़ दी थीं. इसकी लागत का कोई हिसाब ही नहीं रह गया था. नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन सब पर ध्यान दिया.

इसके अलावा मोदी सरकार ने जनधन, मुद्रा, स्टार्टअप, कौशल विकास, मृदा परीक्षण, ग्राम ज्योति, उज्ज्वला, ग्राम स्वराज, डिजिटल, फसल बीमा, स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया आदि अनेक योजनाओं के द्वारा लोक कल्याण को अभूतपूर्व ढंग से बढ़ावा दिया है. बाइस करोड़ लोग निःशुल्क योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं.

स्टार्टअप अब लोगों को आत्मनिर्भर बना रहा है. अबतक करीब आठ सौ स्टार्ट अप का पंजीकरण हुआ है और सरकार ने दस तरह के स्टार्ट अप को टैक्स से छूट दिया है. मुद्रा योजना गरीबों को सशक्त बनाने की दिशा में कारगर साबित हो रही है. दस लाख रुपये तक का बैंकों से उधार लेने की व्यवस्था है. इस योजना ने छोटे कारोबारियों की दुनिया रोशन कर दी है. मुद्रा योजना से साढ़े आठ करोड़ उद्यमी लाभ उठा चुके हैं. तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बांटे जा चुके हैं.

प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत गरीबों को बैंकों में मुफ्त में और आसानी से खाता खुला है. इस स्कीम के तहत अबतक करीब 31 करोड़ से अधिक नए खाताधारक बैंकिंग सिस्टम में जुड़े हैं, जिन्होंने इससे पहले बैंक का मुंह नहीं देखा था. ये योजना जहां एक तरफ गरीबों को सशक्त करने का काम कर रही है, वहीं इस योजना के जरिये क्रियान्वित हुए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के चलते भ्रष्टाचार के एक बहुत बड़े रास्ते को सरकार ने हमेशा-हमेशा के लिए बंद कर दिया है. इन खातों में आज के दिन लगभग पैसठ हजार करोड़ रुपये जमा हैं.

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत आजादी के बाद से जो गांव बिजली के लिए तरस रहे थे, वह रोशन

हुए हैं. मोदी सरकार महंगाई को कम करने और महंगाई दर को यथावत रखने में कुल मिला कर सफल रही है. प्रधानमंत्री उज्जंवला योजना में गरीब परिवार की महिलाओं को केंद्र सरकार की ओर से निशुल्क एलपीजी कनेक्शन दिए जाने की व्यवस्था है. इस स्कीम के तहत कुल पांच करोड़ गरीब परिवारों के एलपीजी कनेक्शन दिए जाने थे, जिसमें से अब तक इस स्कीम के तहत लगभग तीन करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटे जा चुके हैं. इसकी सफलता को देखते हुए सरकार ने इसके पांच करोड़ के लक्ष्य को बढ़ाकर आठ करोड़ कर दिया है.

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान का भी सकारात्मक प्रभाव हुआ है. सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बड़ी संख्या में लोग खाता खुलवा रहे हैं. सरकार लोगों को सस्ते घर बनवाकर भी दे रही है और घर खरीदने में भी मदद देने को तैयार बैठी है. मोदी सरकार की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से ये योजना भी एक है. इसके तहत शहरों में अबतक करीब सात लाख पक्के घरों का निर्माण हो चुका है, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये योजना पूरे युद्धस्तर पर जारी है.

आज देश में एक भी ऐसा गाँव नहीं हैं, जहां बिजली नहीं पहुँची है. हर गाँव में बिजली पहुंचाने के बाद अब मोदी सरकार ने सौभाग्य योजना के तहत हर घर में बिजली पहुंचाने का बीड़ा उठाया है. इसके अलावा अगले चार वर्ष में देश के हर गरीब को छत देने का लक्ष्य हासिल हो जाएगा. इस योजना के तहत एक करोड़ घर दिए जा चुके हैं. उज्ज्वला योजना के तहत साढ़े तीन करोड़ से अधिक मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किये जा चुके हैं, जबकि सरकार ने आठ करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है.

स्वच्छ भारत अभियान का व्यापक प्रभाव हुआ है. इस योजना के तहत देशभर के गांवों में करीब चार करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण हुआ है और लगभग दो लाख गांव खुले में शौच से मुक्ति पा चुके हैं, जबकि शहरों में इकतीस लाख से अधिक घरों में शौचालयों का निर्माण कराया गया है और एक लाख पन्द्रह हजार से ज्यादा सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया है.

मिशन इंद्रधनुष योजना के जरिये बच्चों और माताओं का टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया जा रहा है. ट्रिपल तलाक से मुक्ति का अभियान भी मोदी सरकार ने शुरू किया है और हज पर महिलाओं को यात्रा की छूट दी गई है. सेतु भारतम योजना के तहत लगभग इक्कीस हजार करोड़ रुपये की लगत से सभी नेशनल हाइवे को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाया जा रहा है, जिसे अगले वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा.

भारत आज विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढने वाली अर्थव्यवस्था है, महंगाई दर काबू में है और विदेशी मुद्रा भंडार अपने रिकॉर्ड स्तर पर है. नोटबंदी और जीएसटी, दो ऐसे फैसले हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को पारदर्शी अर्थव्यवस्था के रूप में तब्दील करते हुए व्यापक सुधार लाने में कामयाब रहे हैं.

मोदी के नेतृत्व में विश्व मंच पर भारत की मान-प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई है. दाभोस के मंच पर प्रधानमंत्री का उद्घाटन भाषण विश्व मंच पर भारत के बढ़ते साख की बानगी बयान करता है. सऊदी अरब, फलस्तीन और अफगानिस्तान में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है, यह देश की जनता का सम्मान है. मोदी के एक आह्वान पर योग को पूरे विश्व ने अपनाया है और यूनेस्को ने कुंभ मेले को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थान दिया है. जाहिर है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने चार वर्षों में लोक कल्याण की योजनाओं को सफलता पूर्वक लागू किया है. यह सरकार की नेकनीयत का परिणाम है कि अब योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक ईमानदारी से पहुंच रहा है. सरकार ने बीच के छिद्र बन्द कर दिए हैं, जहां से धन निकल कर घोटालों की भेंट चढ़ जाता था.

इसके अलावा केंद्र सरकार ने कार्य संस्कृति में भी बदलाव किया है. अनेक योजनाएं तो घोषित समय से पहले ही पूरी हो गई. पहले केवल लागत मूल्य बढ़ाने के लिए योजनाएं लंबित छोड़ दी जाती थीं. चार वर्ष में मोदी ने वह माहौल बना दिया है, जिस पर चल कर भारत विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है.

(लेखक हिन्दू पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं. ये उनके निजी विचार हैं.)

सुधार की सही राह पर रेलवे, नए क्षितिज पर ले जाने के लिए ढांचागत सुधार की जरूरत

Credit : www.naidunia.jagran.com

अश्विनी लोहानी

रेलवे को इसका अहसास हुआ है कि उसे सुधार, पुनर्गठन और नई ऊर्जा से लबरेज होने की जरूरत है. यात्री सेवाओं के साथ-साथ माल ढुलाई के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है. जहां सुरक्षा पर पर्याप्त रूप से ध्यान दिया जा रहा है वहीं कार्यसंस्कृति, प्रक्रिया और ढांचागत सुधारों को लेकर भी सही दिशा में कदम बढ़े हैं. रेल तंत्र में सुधार को लेकर इतिहास में शायद पहली बार इतने बड़े कदम उठाए जा रहे हों. फिलहाल रेलवे का पूरा ध्यान अपेक्षित नतीजे देने पर केंद्रित है. सुरक्षा की दृष्टि से वर्ष 2017-18 रेलवे के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा. इस दौरान 73 रेल हादसे ही दर्ज किए गए. यह पहला ऐसा साल रहा जब इन हादसों की संख्या ने सौ का आंकड़ा पार नहीं किया और वे दहाई अंकों में ही सिमट गए. इस उपलब्धि के पीछे समूचे संगठन की सक्रियता है. इस दौरान 4,405 किलोमीटर पुरानी और खतरनाक हो चुकी रेल लाइनों की मरम्मत का काम किया गया. यह किसी भी साल का सबसे ऊंचा आंकड़ा है. 2016-17 के 2,597 किमी के आंकड़े से यह काफी अधिक रहा. बीते चार वर्षों के दौरान 5,469 मानवरहित क्रासिंग से भी निजात मिली है जहां अक्सर हादसे होते रहते थे.यह भी ध्यान रहे कि रेलवे ने अरसे से लंबित और सुरक्षा से जुड़े तकरीबन एक लाख पदों पर भर्तियां की हैं. सुरक्षा के मोर्चे पर खर्च के लिए भी एक लाख करोड़ रुपये का विशेष कोष भी बनाया है. बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर खाई को पाटने के लिए उठाए गए कदमों के फायदे भी दिखने शुरू हो गए हैं. पिछले चार वर्षों के दौरान औसतन वार्षिक पूंजीगत व्यय 98,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा जो उससे पिछले पांच वर्षों में इस मद में हुए व्यय का दोगुना है. पिछले चार वर्षों में रेलवे ने 9,528 किमी लंबी नई ब्रॉड गेज लाइन बिछाई है जो उससे पिछले पांच वर्षों के 7,600 किमी के आंकड़े से अधिक है. यह बुनियादी ढांचे के तेजी से निर्माण की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. विद्युतीकरण भी तरक्की का एक प्रमुख पैमाना है. बीते वित्त वर्ष 4,300 किलोमीटर लाइन का विद्युतीकरण किया गया. विद्युतीकरण के अभियान को आगे और तेजी

दी जाएगी. रेल डिब्बों और इंजनों के निर्माण में भी खासी तेजी आई है. वर्ष 2017-18 के दौरान इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री में 2,397 नए कोच बने तो चितरंजन लोकोमेटिव वर्क्स ने 350 इलेक्ट्रिक इंजन और डीजल लोकोमेटिव वर्क्स ने 321 डीजल इंजन बनाए. 14 सितंबर 2017 भारतीय रेल के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी समकक्ष शिंजो आबे के साथ गुजरात में देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशिला रखी.

भारत के नागरिक और रेलवे से जुड़े होने के कारण यह मेरे लिए बेहद गौरव का क्षण था. रेलों की रफ्तार के मामले में यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी. अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन के जरिये यात्रा में वायु मार्ग से भी कम समय लगेगा. 2023 में पूरी होने वाली इस परियोजना के साथ ही भारत उन खास देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जो तेज गति वाली रेलगाड़ियों के संचालन में सक्षम हैं. इससे न केवल रेल सफर के मोर्चे पर क्रांतिकारी बदलाव आएगा, बल्कि पर्यटन को भी तेजी मिलेगी. इसका तमाम काम 'मेक इन इंडिया' के दायरे में होने से अर्थव्यवस्था को भी बहुत फायदा होगा. भारत और जापान के बीच हुए करार में मेक इन इंडिया और तकनीकी हस्तांतरण का स्पष्ट रूप से उल्लेख है. इससे दूरदराज के इलाकों को भी प्रमुख शहरों से जोड़ने की संभावनाएं बढ़ेंगी और इस तरह बुलेट ट्रेन नए भारत के निर्माण में एक अहम पड़ाव साबित होगी.यह भी उल्लेखनीय है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण भी गति पकड़ रहा है. इस राह में प्रबंध, अनुबंध और कानूनी मोर्चे पर आ रही तमाम अड़चनों को सुलझा लिया गया है और मार्च 2020 में ईस्टर्न एवं वेस्टर्न, दोनों कॉरिडोर एक साथ तैयार हो जाएंगे. रेलवे के लिए यह ऊंची छलांग होगी. हाल के दौर में शुरू किए गए कुछ अभियानों में से एक स्वच्छता की दिशा में भी काफी प्रगति हुई है. हालांकि इस मोर्चे पर अभी भी बहुत सुधार किए जाने की जरूरत है, फिर भी स्टेशनों और रेलगाड़ियों में स्वच्छता के पैमाने पर बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं. इनके अलावा कैटरिंग, रेलगाड़ियों की देरी पर यात्रियों को सूचना, ई-टिकटिंग और पीओएस मशीनों जैसी सुविधाओं को भी तेजी से सिरे चढ़ाया जा रहा है. यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए तेजस, अंत्योदय और हमसफर जैसी रेलगाड़ियों में नई किस्म के डिब्बे लगाए गए हैं. रेलवे ने उपनगरीय रेल सेवाओं को भी उन्नत बनाने का फैसला किया है. मुंबई उपनगरीय रेल सेवा पर 51,000 करोड़ रुपये और बेंगलुरु उपनगरीय रेल सेवा पर 17,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी ताकि करोड़ों मुसाफिरों को उसका फायदा मिल सके. राष्ट्रीय एकीकरण में रेलवे की प्रतिबद्धता को कभी भी कम करके नहीं आंका जा सकता. पिछले चार वर्षों के दौरान 970 किमी गेज रूपांतरण हुआ है और पूर्वोत्तर भारत उस ब्रॉड गेज के साथ जुड़ा जो पूरे देश में फैला है. मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्य भी अब रेल संपर्क से जुड़ गए हैं. इसके साथ ही अरुणाचल में ईटानगर और असम में सिल्चर से नई दिल्ली के बीच सीधी रेल सेवा भी शुरू हो गई है.भारतीय रेल असल में वह पहिया है जो पूरे देश को गति देता है. इसे देश की आर्थिक जीवनरेखा भी कहा जा सकता है. यह आम आदमी की पहुंच वाला आवाजाही का सबसे किफायती माध्यम तो है ही. वर्ष 2014 में नई सरकार के कमान संभालने के बाद से रेलवे के कायाकल्प की दिशा में जो अनेक कदम उठाए गए हैं उनके मूल में सुधार ही हैं, फिर भी इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि रेलवे आंतरिक विरोधाभासों को बयान करने वाला संस्थान है, क्योंकि एक ओर यह कारोबारी उद्यम है तो दूसरी ओर एक मंत्रालय भी. ऐसे में यह अपनी पूरी संभावनाओं को नहीं भुना पाता. इसे नए क्षितिज पर ले जाने के लिए ढांचागत सुधार करने ही होंगे और यह जितना जल्दी हो, उतना बेहतर. परिवर्तन हमेशा कुछ परेशानी पैदा करता है, लेकिन किसी भी संस्थान को इसके लिए तैयार रहना चाहिए. अगर यह बेहतर भविष्य के लिए हो तो वर्तमान में कुछ तकलीफ झेलने में कोई बुराई नहीं. हाल के दौर में हुई प्रगति खासी उल्लेखनीय है, लेकिन इससे भी इन्कार नहीं कि हम अपनी अपेक्षाओं से पीछे हैं. अपेक्षाओं और परिणामों में चौड़ी होती खाई से यह अंतर और बढ़ता जाएगा. दरअसल स्थिति तब तक नहीं सुधरेगी जब तक रेलवे को पूरी तरह पेशेवर ढंग से चलाने के लिए हो रहे बड़े ढांचागत सुधार आकार नहीं ले लेते. सुधार प्रक्रिया को लेकर जताई गई प्रतिबद्धता से यह स्पष्ट है कि रेलवे देश के आर्थिक विकास में हमेशा एक प्रमुख किरदार बना रहेगा.

(लेखक रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, दैनिक जागरण से साभार)

Four years of Narendra Modi govt: A pithy and cool micro-site tells and sells 48-month success story

Samir Sachdeva

MyGov.in, a micro-site that presents the National Democratic Alliance (NDA) government's achievements over 48 months, is creating waves in online space. The reasons gives us a peek into Narendra Modi's style of functioning.

Government websites are meant for informing the citizens and carrying out online services but these carried such an ill-repute of inefficiency and dullness that none except the dogged or desperate dared venture its corridors. Navigating the bad form, dreary content, outdated information, missing data or broken links tested the limits of patience.

Overhauling the government's image has been a key focus area of Modi. The micro-site turns on its head the concept of government websites in its basic parameters of presentation, information and engagement and shows how data can be used to tell and sell a story of success.

The UPA released its annual report cards through the Press Information Bureau, which was the online concept of handing those who wanted to know about the government, a sheaf of papers and then leaving them to their fate. It indicated the government's fatalism that no one would be interested in knowing its progress reports. Modi not only believes that he has a story to tell, he also seeks active engagement from citizens. He reckons they would be interested in knowing exactly what he has done and achieved over 48 months.

The micro-site catches this fundamental difference in thinking by focusing on easy navigation (not too many boxes, links and sidebars), sleek interface and stunning info-

graphics. Consequently, MyGov.in has less clutter, no dead links or irritating pop-ups. Users have the option of viewing info-tiles in English or Hindi via a drop-down menu that reflects attention to detail.

The showstopper, however, is the Performance Dashboard that shows the impact of various Central schemes and initiatives through figures that seemingly update in real time. The prime minister's aim is to tell the citizens in a nutshell what he has done and achieved over a period of four years in the areas of Direct Benefit Transfer (DBT), Jan Dhan Yojana, Ujjwala Yojana, Atal Pension Yojana, Mudra Yojana, PM Awas Yojana, LED distribution scheme, length of road constructed (in km) under the Gram Sadak Yojana since fiscal 2013-14, etc, with one tile mentioning a 'zero' to denote the number of un-electrified villages.

Apart from the visual effect which catches immediate attention, the Performance Dashboard in MyGov.in serves two purposes. One, it is Modi's way of letting the electorate know that he has not wasted his mandate and has used resources judiciously to effect structural reforms. Two, it reveals the prime minister's conviction that media will not convey to people the work that he has done, and therefore he must take it upon himself to share the story.

The government's focus areas clearly defined on top in form of Accelerating Growth, Commitment to Social Justice, Development for All, Eliminating Corruption, Harnessing Yuva Shakti, Healthy India, Infrastructure for New India, Putting Farmers First, Speed and Scale of Transformation, The World Sees a New India, and Women Led Development.

Clicking on these tabs open a page where blogs by Union ministers are displayed along with relevant infographics. For instance, while 'Eliminating Corruption' leads to 'Use of Technology to Boost Transparency', 'Greater Formalization for a Healthier Economy', etc., 'Putting Farmers First' opens to 'Fertilizer Units to Boost Production', etc.

While these are hardly groundbreaking navigation tools, it is a welcome change to see the method being applied in a government website.

Some of the minister who have contributed blogs include Maneka Gandhi, Radha Mohan Singh, Harsimrat Kaur Badal, DV Sadananda Gowda, Suresh Prabhu and others. This lends a personal touch and an informality which is further reinforced with video testimonials from beneficiaries of flagship government schemes. In one of the clips, for instance, Karthik Chandrashekar of AIC-Sangam Innovation Foundations talks about Atal Innovation Mission and how it is helping entreprenuers.

The download centre has e-books, flyers, images, print ads, and clips that may be shared and downloaded. The focus remains on key achievements in 48 months.

The site is pithy, sexy, colorful and takes an unconventional way to sharing statistics. It works on a concept that bombarding the user with too many data at starting point might make it confusing and counterproductive. The user might feel disinterested or overwhelmed. Here, the minimalistic yet sleek design attracts the casual as well as serious users.

People who have a short attention span might still feel interested to browse the information since it is presented in an appealing way (and may feel encouraged to explore more) while researchers, journalists, policymakers and other interested citizens may feel relieved at the clutter-free presentation that allows them to dig deep and access data without wasting huge amount of time in navigation.

(This Article was first published in FirstPost)

Modi government at four years: It has pushed through a range of structural reforms whose results will show

Credit : www.mapof india.com

Arvind Panagariya

Progress in reforms is like the movement of the hour hand of the clock: human eye is unable to detect the movement in it and yet it has gone full circle twice a day. While naysayers complain that they can see no progress in reforms, reforms in the past four years have accumulated to the point that only highlights can fit a newspaper column.

During the last two full fiscal years of the United Progressive Alliance (UPA) government, inflation had averaged 9.7% and growth 5.9%. To address inflation, the new government adopted inflation targeting on the monetary front and a strict fiscal consolidation plan on the fiscal front. To address growth, it undertook numerous structural reforms. The result has been an average inflation rate of 4.3% and GDP growth of 7.3% during the past four years.

Governance has been a key focus of the government. The government's concerted efforts towards improving the ease of doing business have translated into India jumping from 140th to 100th position in the World Bank rankings. In parallel, the government has worked to improve the ease of living. Citizens no longer need to have copies of degrees and diplomas certified by a Gazetted Officer; they may store soft copies of their degrees and diplomas in DigiLocker; and they may access many central and state services online through portal Umang. Forty million BPL households have received LPG connections under Ujjwala Yojana.

The government is working to end corruption on a war footing. Demonetisation, a daring act, was an integral part of this effort. It has yielded handsome dividend through many channels: detection and closure of lakhs of shell companies;

disqualification of lakhs of company directors; destruction of black wealth in real estate through a sharp decline in prices; rise in the number of income tax payers; and transmission of a strong signal of the government's resolve to combat corruption.

Replacement of the Planning Commission by Niti Aayog has been a major institutional innovation. The new institution has emerged as an active promoter of the prime minister's reform agenda. It has also forged a more cordial and equal relationship with the states.

The second set of reforms demonstrates the ability of the government to do programmes on scale. Three initiatives in this category stand out: Aadhaar, Jan Dhan Yojana (JDY) and Swachh Bharat Mission (SBM). Aadhaar cards have risen from 650 million in March 2014 to 1.2 billion. At peak, the government issued 8.65 million cards in August 2017 alone. Under JDY, 18 million bank accounts were opened in one week during August 23-29, 2014, a feat that found mention in the Guinness Book of World Records.

Today, the total number of JDY accounts stands at 316 million. Finally, under SBM, rural households with toilets in their homes have risen from barely 38% to 84.2% with 17 states declared open defecation free in rural areas. We are now within striking distance of ending open defecation by October 2, 2019, 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi.

Important structural reforms include deregulation of petrol and diesel prices, further opening to foreign direct investment (FDI), shift to direct benefit transfers (DBT), the Goods and Services Tax (GST), Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) and academic and administrative autonomy to top universities and colleges. On petrol and diesel prices, the government must be applauded for refusing to reverse the reform despite political pressure from all sides. On FDI, the opening up in e-marketplace promises a major overhaul of retail marketing in India. The shift to DBT using Aadhaar instrumentality has led to the elimination of vast number of ghost beneficiaries.

Various criticisms around its implementation notwithstanding GST reform, which required a constitutional amendment and multiple legislations, constitutes a landmark achievement of the government. With a single nationwide tax replacing a vast number of state and central taxes, we can count on major efficiency gains. Already, the movement of commercial vehicles along highways has speeded up by 15% on average.

I have lamented, for nearly two decades, that India lacks a modern bankruptcy law. IBC has finally filled this glaring gap. Building on it, the Reserve Bank of India (RBI) circular of February 12, 2018, has modernised regulations governing recovery of bank loans. This reform will go a long way towards solving the recurrent problem of non-performing assets (NPAs). As the case of Bhushan Steel illustrates, RBI is also successfully deploying IBC to clean up existing NPAs.

Despite their launch nearly three decades ago, reforms had left untouched the area of higher education. That too has been addressed now with the government giving unprecedented academic and administrative autonomy to our top universities and colleges. The reform will stimulate much needed competition among our academic institutions.

One area in which the government has erred, however, is international trade. Decades of efforts to liberalise trade by governments led by both BJP and Congress have been reversed, with hikes in customs duties on a large number of products. We have also failed to forge any market opening free trade agreements with our trading partners. The next government will need to do course correction in this important area.

(This Article was first published in The Times of India)

My Reflections on the NDA Government after Completion of Four Years in Power

Arun Jaitley

The NDA Government led by Prime Minister Narendra Modi has completed four years in office. Today it enters its fifth year in office.

The Change

The preceding ten years of the UPA rule had unquestionably witnessed the most corrupt Government since Independence. Prime Minister Narendra Modi created transparent systems through legislative and institutional changes which have given this country a scam-free governance. Unlike the UPA, the Prime Minister is the natural leader of both his party and the nation. We have witnessed a journey from indecisiveness to clarity and decisiveness. India has transformed from being a part of the "fragile five" to the "bright spot" on the global economic scene. A regime of policy paralysis has been transformed into one of decisions and actions. India, which was on the verge of becoming a "basket case" has today been transformed into the fastest growing major economy in the world and is likely to hold that position in the years to come. The country's mood from despair has transformed into hope and aspirations.

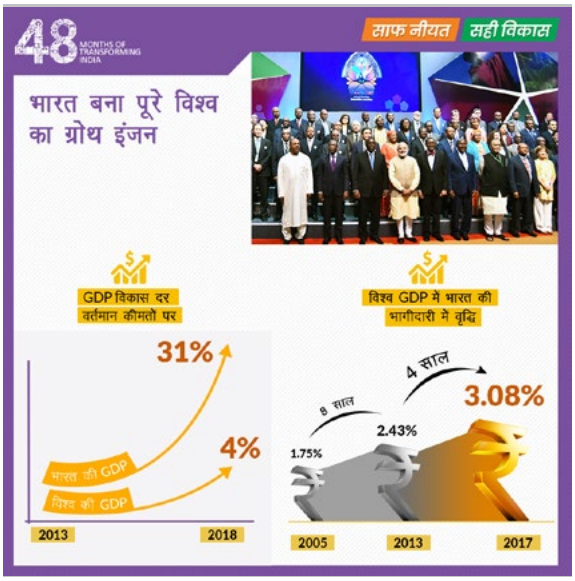

Good governance and good economics have been blended with good politics. The result of this has been that the BJP is more confident, its geographical base has become much bigger, its social base has expanded and its winnability has hugely increased. The Congress is in desperation without the perks of office. From the dominant party of Indian politics, it is moving towards the "fringe", its political positions are not of a mainstream party but one usually adopted by "fringe" organisations. Fringe organisations can never hope to come in power. Its best hope lies in becoming a supporter of regional political parties. State level regional political parties have realised that the marginalised Congress can at best be either a junior partner or a marginal supporter. Karnataka had witnessed a telling example of this. A regional political party whose base at best is confined to a few districts was able to extract a Chief Ministership of the Congress to which the Congress meekly surrendered. It had even lost its bargaining capacity. It is today putting on a brave face in Karnataka where the losers are masquerading as a winner.

Scam-free Governance

Prime Minister Modi has institutionalised a system where discretions have been eliminated. Discretions lead to abuse of power because they can be misused. Allocations of contracts, natural resources, spectrum and other Government largesse which were being distributed through discretions, are now allocated through a market mechanism. Laws have been changed. Leaders of the industry are no longer seen repeatedly visiting the South Block, the North Block or the Udyog Bhawan. Environmental clearance files don't pile up. FIPB has been abolished.

For cleaning up the economy, India has to transform from a tax non-compliant society to a tax-compliant society. The enactment and implementation of the Goods and Services Tax, the impact of demonetisation, effective tax compliance are all steps against black money, steps which are formalising the Indian economy. The Insolvency and Bankruptcy Code has changed the lender-creditor relationship. The creditors no longer have to chase the debtors. If you cannot pay your creditors, you have to exit through a statutory mechanism.

The Social Sector Priority

For the first time in history, the poor and the marginalised are holding bank accounts as part of the world's largest financial inclusion programme. The MUDRA Yojana has made cheaper credit available to the weak and the marginalised. The biggest beneficiaries of this have been women, SC/ST, minorities and other weaker sections. Rural roads with a hugely increased expenditure are a success story. That every village must be connected with road and electricity, affordable rural housing, toilets and gas connections in all homes, are intended to change the quality of

life in villages. The Crop Insurance Scheme and the Government's decision that farmers must get 50 percent above cost are steps intended to eliminating agricultural distress. The UPA Government had sanctioned Rs.40,000 crores under MGNREGA but with budget cuts spent only Rs.29,000 crores. Today that expenditure has been doubled. Under Food Security Programme, the expenditure has been increased to Rs.1,70,000 crores to ensure cheaper food-grain availability to the eligible. On the healthcare front, the destiny of India's poor will change when 40 percent families at the bottom of the ladder will get a treatment upto rupees five lakhs for hospitalisation at the cost of the Government scheme.

The Economic Management

During the UPA Government, India had fallen off the global radar. In its initial years when the world economy was booming, India grew on the strength of global tailwinds. When the global situation became challenging, the UPA's decisiveness and performance collapsed. The last two years of the UPA had witnessed substantially lower growth rates. From the very first year of NDA, India is the world's fastest growing major economy with the highest GDP growth rates. This is also the global projection for the next few years.

The Current Account Deficit (CAD) saw an unprecedented 6.7 percent deficit in the year 2012-13. The NDA has consistently maintained a CAD of under 2 percent on an annualised basis. The poor economic management was visible when under the UPA fiscal deficits remained alarmingly high. The Government was spending more and earning less. We witnessed fiscal deficits of 5.8 percent, 4.8 percent and 4.4 percent in the UPA's last three years. Having inherited the mess, the NDA, year after year, has brought it down to 3.5 percent and shall, this year, try and deliver a 3.3 percent fiscal deficit. The UPA's economic management was such that even when fiscal deficits were high, expenditure cuts of over rupees one lakh crores were done in order to make fiscal deficit optically look slightly better. Cut in expenditure means cut in growth. During the NDA years, Revised Estimates of expenditure were always been higher than Budget Estimates. The UPA provided India in its last years an inflation figure upto 9 percent and at one stage even crossed into double digits. The NDA has tried to contain inflation and on most occasions has remained within the target of 3 to 4 percent. The poor economic management of the UPA resulted in the high cost of borrowing for the Centre and the State Governments. The bond yields had touched an incredible 9.12 percent in April, 2014. We have been, on an average, able to contain it between 6 to 7 percent with a low of 6.3 percent on one occasion and rarely in the 7 percent range only when global factors impacted either the currency or the crude prices.

From the last year of the UPA, the infrastructure expenditure to this year has increased by 134 percent during the current year. The Congress President must remember that taxes don't go into the pocket of the Government. They go back to the people for better infrastructure, better social sector expenditure and poverty reduction programmes. The social sector expenditure has seen a substantial increase by both the Central and the State Governments. The road sector programmes has witnessed a 189 percent increase between the last year of the UPA and the current year of the present Government. Resources are transferred to the States with 42 percent devolution of taxes,

Finance Commission grants and assistance through the CSS schemes. Notwithstanding the perpetual grumbling, last year of the UPA witnessed Rs.5,15,302 being transferred to the States. This year the proposed transfer is 145 percent higher and will be at 12,62,935. crores. This is over and above what the States earn from the GST where they have been constitutionally protected with a 14 percent annual increase. The States independently levy their own taxes.

Institutional changes thus being enacted and implemented are putting the Indian economy on a far stronger wicket.

The Fifth Year Debate

As we enter the fifth year of the Government, the NDA's priorities are clear. This will be our year of consolidation of the policies and programmes which we have implemented. In our Prime Minister, we have a strong leader with a mass appeal. His capacity to change India's destiny is globally recognised. His insistence on integrity, his infatigable capacity to work, his clarity of policy and direction, his boldness in taking steps in larger national interest gives the NDA a natural political advantage. Clarity and credibility are hallmarks of the NDA Government.

The last few days have witnessed a discussion about a "fictional alternative". A group of disparate political parties are promising to come together. Some of their leaders are temperamental, the others occasionally change ideological positions. With many of them, such as TMC, DMK, TDP, BSP and the JD(S), the BJP has had an opportunity to share power. They frequently change political positions. They have supported the BJP claiming that it is in larger national interest and then turned turtle and oppose it in the name of secularism. These are ideologically flexible political groups. Stable politics is far from their political track record. Some amongst this disparate group have an extremely dubious track record of governance. Some leaders are maverick and others include those who are either convicted or charged with serious allegations of corruption. There are many whose political support base is confined to either a few districts or to a particular caste. To rule a large country like India through coalitions is possible but the nucleus of a coalition has to be stable. It must have a large size, an ideologically defined position and a vested interest in honest governance. A federal front is a failed idea. It was experimented under Shri Charan Singh, Shri Chandrasekhar and by the United Front Government between 1996-98. Such a front with its contradictions, sooner or later, loses its balance and equilibrium. Remembering 1996-98 as perhaps one of the worst period of governance, the aspirational India which today occupies the high table in the world shall never accept an idea which has repeatedly failed. History teaches us this lesson. Aspirational societies with vibrant democracies do not invite anarchy. A strong nation and the requirements of good governance abhor anarchy. The political agenda for the debate this year appropriately will be Prime Minister "Modi versus an anarchist combination". The 2014 election conclusively established that in the New India chemistry will score over arithmetic when it comes to deciding the country's destiny.

(The Author is Minister of Finance, Govt of India Courtesy: Arun Jaitley's Facebook Page)

48 MONTHS OF TRANSFORMING INDIA
change
ward districts
cross the country
सत्यमेव जयते
Prime Minister's
Rural Development Fellows
प्रधान मंत्री ग्रामीण विकास फेलोज़
Scripting Change
PRIME MINISTER
Chairperson, TISS

IDFC
IDFC BANK
48 MONTHS OF TRANSFORMING INDIA
IDFC Bank
IDFC आई डी एफ सी बैंक
PRATHAM
6084 3579 2468 1804
10/15
09/20
SAKHI SHAKTI
1234 5678 9012
RuPay
DEBIT

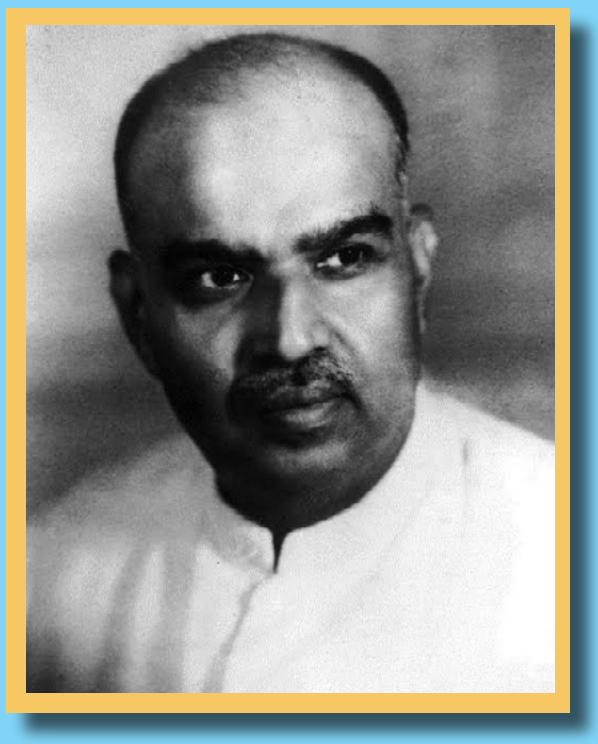

"The gigantic task of reconstruction, cultural, social, economic and political can be rendered possible thought coordinated efforts of bands of trained and disciplined efforts of bands of trained and disciplined Indians. Armed with the knowledge of Indian's past glory and greatness, her strength and weakness, it is they who can place before their country a programme of work, which while loyal to the fundamental traditions of India civilisation will be adapted to the changing conditions of the modern world."

-Dr. Syama Prasad Mookerjee
Convocation Address delivered at Gurukul Kangri Viswavidyalaya, Haridwar, 1943

Published By:
Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation
9, Ashoka Road New Delhi - 110001
E-mail: office@spmrf.org, Phone: 011-23005850